

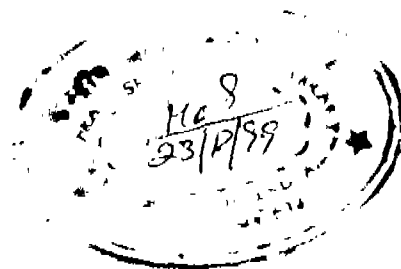


भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 231]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 18, 1999/आश्विन 26, 1921

No. 231]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 18, 1999/ASVINA 26, 1921

वाणिज्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अक्तूबर, 1999

विषय : अमरीका, जर्मनी जनवादी गणराज्य, चेक गणराज्य, कोरिया गणराज्य और यूरोपियन संघ क्षेत्र से सोडियम सॉयनाइड के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जाँच : आरंभिक निष्कर्ष।

आरंभिक निष्कर्ष

सं. 8/1/99-डीजीएडी.—सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम (1995 में यथा संशोधित), 1975 तथा उसकी सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान उक्त पर पाटन-रोधी शुल्क का आकलन एवं समाहरण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 का ध्यान करते हुए :

क. पद्धति

1. जाँच के लिए नीचे वर्णित पद्धति का पालन किया गया है :—

- नाम निर्दिष्ट प्राधिकारी ने (जिसे इसमें इसके बाद प्राधिकारी कहा गया है) नियमावली के अंतर्गत, स्वदेशी उद्योग की ओर से मै. सॉयनाइड्स एंड कैमिकल्स कं. से अमरीका, जर्मनी जनवादी गणराज्य, चेक गणराज्य, कोरिया गणराज्य और यूरोपियन संघ क्षेत्र मूल के या वहां से निर्यातित सोडियम सॉयनाइड के पाटन का आरोप लगाते हुए लिखित आवेदन प्राप्त किया;
- वादी द्वारा दी गई याचिका की आरंभिक जाँच से कतिपय त्रुटियों का पता चला जिन्हें बाद में वादी द्वारा ठीक कर दिया था। अतः याचिका को सही सही विलेखित माना गया था;
- वादी द्वारा दिए गए पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर प्राधिकारी ने अमरीका, जर्मनी जनवादी गणराज्य, चेक गणराज्य, कोरिया गणराज्य और यूरोपियन संघ क्षेत्र से सोडियम सॉयनाइड के आयातों की जाँच करने का निश्चय किया।
- प्राधिकारी ने जाँच आरंभ करने से पहले, नियमावली के नियम 5(5) के अनुसार पाटन के आरोप के प्राप्त होने की सूचना अमरीका, जर्मनी जनवादी गणराज्य, चेक गणराज्य, कोरिया गणराज्य और यूरोपियन संघ क्षेत्र के दूतावासों को दी,

- v. प्राधिकारी ने सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के सीमा शुल्क उपशीर्ष सं. 2837.11.00 के अंतर्गत वर्गीकृत अमरीका, जर्मनी जनवादी गणराज्य, चेक गणराज्य, कोरिया गणराज्य और यूरोपियन संघ क्षेत्र (जिन्हें इसमें इसके बाद विषयगत देश कहा गया है,) मूल के या वहां से निर्यातित सोडियम सॉयनाइड के आयातों के बारे में पाटन-रोधी जाँच आरंभ करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में एक सार्वजनिक सूचना तारीख 8 मार्च, 1999 प्रकाशित कर जारी की;
- vi. प्राधिकारी ने सार्वजनिक सूचना की एक प्रति ज्ञात निर्यातकों (जिनके विवरण वादी द्वारा उपलब्ध कराए गए थे) एवं उद्योग संघों को भेजी और नियम 6(2) के अनुसार उन्हें अपने विचार बताने का अवसर प्रदान किया;
- vii. प्राधिकारी ने भारत में सोडियम सॉयनाइड के ज्ञात आयातकों को (जिनके विवरण वादी द्वारा उपलब्ध कराए गए थे) सार्वजनिक सूचना की प्रति भेजी और उन्हें पत्र की तारीख से चालीस दिनों के भीतर अपने विचार लिखित रूप में देने के लिए कहा;
- viii. आबकारी एवं सीमा-शुल्क केन्द्रीय बोर्ड (सीबीईसी) से जाँच की अवधि सहित पिछले तीन वर्षों के सोडियम सॉयनाइड के आयातों के विवरण देने का अनुरोध किया गया था;
- ix. प्राधिकारी ने पूर्वोक्त नियम 6(3) के अनुसार ज्ञात निर्यातकों एवं भारत में विषयगत देशों के दूतावासों को याचिका की प्रति भेजी। जहाँ कहीं भी मांगी गई, याचिका की एक प्रति अन्य हितबद्ध पार्टियों को भी भेजी गई थी।
- x. प्राधिकारी ने नियम 6 (4) के अनुसार संबंधित सूचना प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित ज्ञात निर्यातकों को प्रश्नावली भेजी :—

(क) यूरोपियन संघ

- * डेगुस्सा एण्टरप्राइज एन. बी., बेल्जियम
- * रहोने-पोलीन फाइबरस—फ्रांस
- * जेनेका एप्रोकैमिकल्स—फर्नहैस्ट
- * बसलीरस पी.ए.—इटली
- * एनीकैम एस. पी. ए., इटली
- * डी एस एम बिजनेस यूनिट एण्टमीडिएट—नीदरलैंड्स
- * एनर्जीआई इंडस्ट्रीज एंरेगोनसस, स्पेन
- * मोनिप्लैट एंड इस्टबार एस एल, स्पेन
- * डेगुस्सा एजी—जर्मनी
- * बी ए एस एफ—अक्विनोशेल्सकाफ्ट—जर्मनी
- * ई मार्क—जर्मनी
- * पेट्रो/केमी बी क्राफ्ट स्टोपी—जर्मनी

(ख) अमरीका

- * ई आई डूपौण्ट दे नेमोर्स एंड कंपनी इंक., अमरीका
- * दगुस्सा कार्पोरेशन, अमरीका
- * एफ एम सी कार्पोरेशन कैमिकल प्रोडक्ट्स, अमरीका
- * स्टर्लिंग कैमिकल इंक., अमरीका
- * सी पी कैमिकल इंक.—अमरीका

(ग) चेक

- * लूशेन्नी जावेदी—चेक गणराज्य

(घ) कोरिया जन. गणराज्य

- * टोंग-सू पैट्रोकेमिकल्स कॉरपोरेशन लिमि—सियोल, कोरिया
- * टेक वांग, सियोल, कोरिया

- xi. नियम 6(2) के अनुसार जांच शुरू होने की सूचना, विषयगत देशों/क्षेत्रों के नई दिल्ली स्थित दूतावासों को इस अनुरोध के साथ भेजी गई कि वे अपने देशों के निर्यातकों/उत्पादकों से निर्धारित समय के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने के लिए कहें। ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों की एक सूची के साथ, पत्र, याचिका एवं निर्यातकों को भेजी गई प्रश्नावली की प्रति दूतावासों को भी भेजी गई।
- xii. अनेक पार्टियों ने समय बढ़ाने का अनुरोध किया था जिसे प्राधिकारी ने चार सप्ताहों के लिए मान लिया। बड़े हुए समय के बाद प्राप्त होने वाले उत्तरों पर, आरंभिक निष्कर्षों के निश्चयन हेतु विचार नहीं किया गया है।
- xiii. निम्नलिखित निर्यातकों ने उत्तर दिया था—

ई. यू.

- * मै. ई. मर्क
- * मै. देगुस्सा हल्स
- * मै. पी सी के रेफिनरी जी एम बी एच

अमरीका

- * मै. स्टर्लिंग कैमिकल्स
- * मै. सी पी कैमिकल्स इंक.

कोरिया

- * मै. हैन्वाह कैमिकल्स कारपोरेशन

- xiv. नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना माँगवाने के लिए सोडियम सॉयनाइड के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों को प्रश्नावली भेजी गई—

- * मै. बकुल एरोमैटिक्स लि.
- * मै. प्रीमियर इंटरमीडिएट्स (प्रा.) लि.
- * मै. यूनाइटेड फॉसफोरस लि.
- * मै. दौराला शुगर वर्क्स
- * मै. दौराला आर्गेनिक्स लि.
- * मै. चेपिनोर ड्रग्स लि.
- * मै. दिविश लेबोरेटरीज लिमि.,
- * मै. सुवेन फार्मास्यूटिकल्स
- * मै. सुदर्शन ड्रग्स इंटरमीडिएट लि.
- * मै. सुवि कैम
- * मै. अनीस रसायन प्रा. लि.
- * मै. श्री बेंजोफन इंडस्ट्रीज लि.
- * मै. मिट्सु इंडस्ट्रीज लि.
- * मै. भारत रसायन
- * मै. डीलक्स मैटल प्रोसैसिंग
- * मै. कैमस्टार आर्गेनिक्स लि.
- * मै. अंकुर एग्रोकैम
- * मै. सिरिस लि.

xv. प्रश्नावली का उत्तर निम्नलिखित आयातकों द्वारा दिया गया—

- * मै. बकुल एरोमैटिक्स लि.,
- * मै. प्रीमियर इंटरमीडिएट (प्रा.) लि.,
- * मै. कैमिनोर ड्रग्स लि.,
- * मै. दौराला आर्गेनिक्स लिमि.,
- * मै. मित्सु इंडस्ट्रीज लिमि.,
- * कोरस इंडिया लिमि.,

xvi. क्षति पर चादियों से अतिरिक्त सूचना मांगी गई थी, जो भी दे दी गई थी;

xvii. प्राधिकारी ने आवश्यक समझी गई सीमा तक वादी के परिसर पर स्थल जाँच की;

xviii. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पार्टियों द्वारा दिए गए साक्ष्यों के अगोपनीय पाठ, प्राधिकारी द्वारा रखी गई सार्वजनिक फाइल के रूप में उपलब्ध कराए गए और उसे हितबद्ध पार्टियों के देखने के लिए खुला रखा;

xix. सामान्य: स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएपीपी) तथा वादी द्वारा दी गई सूचना के आधार पर इष्टतम उत्पादन लागत एवं भारत में विषयगत माल के बनाने एवं बेचने की लागत का हिसाब लगाने के लिए लागत जाँच भी की गई;

xx. यह बिहून् इस अधिसूचना में, एक हितबद्ध पार्टी द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई और प्राधिकारी द्वारा नियमावली के अंतर्गत ऐसी मांगी गई सूचना का द्योतक है;

xxi. जाँच 1 अप्रैल, 1998 से 31 दिसम्बर, 1998 तक की अवधि के लिए की गई थी।

ख. वादी के विचार

2. वादी ने अपनी याचिका एवं बाद के अभिवेदनों में निम्नलिखित मुख्य मुद्दे उठाए हैं:—

(क) जाँच अवधि के दौरान भारतीय उद्योग का कुल उत्पादन 5626 मी.टन जिसमें से वादी की हिस्सेदारी 78.44 प्रतिशत की है। अतः वादी ने कहा है कि उनके द्वारा दिए गए आवेदन को, स्वदेशी उद्योग की ओर से दिया गया माना जाए और उन्हें नियम 2 (ख) के अंतर्गत स्वदेशी उद्योग माना जाए।

(ख) वादी ने आरोपित पाटन करने वाले देशों अर्थात् अमरीका, जर्मन जनवादी गणराज्य, चेक गणराज्य, कोरिया गणराज्य और यूरोपीय संघ के मामले में, उत्पादन की निर्मित लागत के आधार पर सामान्य मूल्य की माँग की है।

(ग) वादी ने माँग की है कि सामान्य मूल्य के निश्चयन के प्रयोजन हेतु यूरोपियन संघ को एक निर्यातक क्षेत्र माना जा सकता है। उन्होंने कहा है कि जर्मनी, यूरोपीय संघ का सदस्य है जहाँ सदस्य देशों के बीच सीमा-शुल्क के रोध नहीं हैं। यूरोपियन संघ में सोडियम सॉयनाइड के अन्य अनेक उत्पादक हैं और इसे देखते हुए, यदि समस्त यूरोपियन संघ पर पाटन-रोधी शुल्क नहीं लगाया जाता है तो केवल जर्मनी पर ही पाटन-रोधी शुल्क लगाया जाना प्रभावी नहीं हो सकता। अतः वादी का अनुरोध, जाँच करने एवं यूरोपियन संघ पर एक क्षेत्र के रूप में संघनित तौर पर एवं जर्मनी जनवादी गणराज्य पर निजी तौर पर पाटन-रोधी शुल्क लगाने का है।

(घ) जहाँ तक क्षति का सम्बन्ध है, इसके लिए वादी द्वारा निम्नलिखित अभिवेदन किए गए हैं—

(i) यह कि वादी, नियम 2 (ख) के अर्थों के अंदर स्वदेशी उद्योग होता है। अतः उनके द्वारा उठाई गई क्षति को, स्वदेशी उद्योग द्वारा उठाई गई आर्थिक क्षति के साक्ष्य के तौर पर माना जाना चाहिए।

(ii) वादी ने निम्नलिखित के कारण क्षति का दावा किया है—

- * विषयगत देशों से आयातों में वृद्धि।
- * विषयगत देशों के निर्यात मूल्यों में भारी गिरावट।
- * आयातों की बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि।
- * वादी के विक्री मूल्यों में भारी गिरावट।
- * लाभकारिता में भारी गिरावट।
- * मालसूची के स्तरों में भारी वृद्धि।

ग. निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पार्टियों के विचार :

3.1 आयातकों के विचार :

- (क) भारत से भारी मात्रा में निर्यात किए जाने वाले एम्पीसीलीन, सेफैलैक्सीन, सेफ्ट्रडिन आदि एण्टीबायोटिक हेतु, औषध मध्यकों के उत्पादन में प्रयोग किए जाने वाले सोडियम सॉयनाइड के निर्यातकों ने कहा है कि सोडियम सॉयनाइड पर लगे आयात शुल्क में वृद्धि से लागत एवं मध्यकों के मूल्य बढ़ जायेंगे, जिसका एण्टीबायोटिक्स के निर्यातों पर भारी विपरीत प्रभाव पड़ेगा। विकल्प के तौर पर स्वदेशी उद्योग द्वारा उत्पादित मध्यक आयातित होंगे जिससे औषध मध्यकों के स्वदेशी उद्योग के हितों की हानि होगी।
- (ख) वादी स्वयं भी स्वदेशी मूल्यों से काफी कम मूल्यों पर विषयगत माल का निर्यात कर रहे हैं। वे इस तथ्य का लाभ उठाना चाहते हैं कि भारत में सोडियम सॉयनाइड के केवल दो ही उत्पादन हैं और इस लिए स्वदेशी मूल्यों को कृत्रिम ढंग से, अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों से काफी ऊँचे स्तर पर रखा गया है। भारत में लगभग एकाधिकार की स्थिति के साथ, आयात शुल्क में किसी भी वृद्धि का परिणाम, औषध एवं औषध मध्यक उद्योगों के भारी अहित में सोडियम सॉयनाइड के स्वदेशी मूल्यों में भारी वृद्धि होगी।
- (ग) सोडियम सॉयनाइड के उत्पादन की लागत, वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों अर्थात् लगभग रु. 38,000 से रु. 40,000 प्रति मीट्रिक टन से अधिक नहीं हो सकती जिस पर वादी स्वयं ही निर्यात कर रहे हैं।
- (घ) इसके अलावा यह कहा गया है कि विषयगत माल के सामान्य मूल्य का हिसाब लगाने के लिए वादी ने निर्मित लागत का प्रयोग किया है। निर्मित मूल्य के प्रयोग की आवश्यकता बाजार रहित अर्थ-व्यवस्थाओं में होती है। वर्तमान मामले में, विषयगत देशों के निर्यातकों से सामान्य मूल्य के विवरण लेने में किसी कठिनाई के आने की संभावना नहीं है।
- (ङ) सोडियम सॉयनाइड के दो उत्पादक हैं, वादी तथा मै. गुजरात अल्कलीन एण्ड कैमिकल्स लि.। दूसरे सह-वादी शायद इसलिए नहीं बने कि वे अधिक कुशल हैं।
- (च) इस बात का पूर्व इतिहास है कि दो स्वदेशी उत्पादक मिलकर एक उत्पादक-संघ बना लेते हैं और सोडियम सॉयनाइड के मूल्यों में अंधाधुंध वृद्धि कर देते हैं, जैसाकि 1991 में किया गया था जब इस उत्पाद का आयात प्रतिबंधित था। उत्पाद पर यदि पाटन-रोधी शुल्क लगाया जाता है तो 1991 का परिदृश्य दोहराया जाएगा।
- (छ) और आगे यह भी कहा गया कि दोनों ही स्थानीय (स्वदेशी) उत्पादकों का वास्तविक उत्पादन, कागजों में बड़ी संस्थापित क्षमता के बावजूद देश की आवश्यकताओं से कम रहा है। विगत में, जब कभी भी उत्पादन अधिक रहा है उसे बहुत नीचे के मूल्यों पर निर्यात कर दिया गया। इसके लिए उच्चतर स्थानीय (स्वदेशी) बिक्री मूल्यों से ही भरपाई की जाती रही है।
- (ज) कुछ उत्पाद जैसे थियोफाइलाइन इटोफाइलीन आदि जिनमें सोडियम सॉयनाइड पड़ता है डीपीसीओ के अन्तर्गत आते हैं तथा उनके मूल्य सरकार द्वारा तय किए जाते हैं। इन उत्पादों के डीपीसीओ मूल्यों का निर्धारण सोडियम सॉयनाइड के चालू मूल्य के आधार पर किया गया है। यदि पाटन-रोधी शुल्क लगाने के परिणामस्वरूप इस सामग्री का मूल्य बढ़ता है तो निर्यातकों को मूल्य बढ़ाने के लिए भारत सरकार से कहना पड़ेगा, जो एक बहुत लम्बी प्रक्रिया है और जिसमें दो साल तक लग सकते हैं।
- (झ) यदि सोडियम सॉयनाइड पर पाटन-रोधी शुल्क लगाया जाता है तो स्वदेशी उत्पादकों द्वारा सोडियम सॉयनाइड के मूल्य बढ़ा दिए जाएंगे और ऐसा होने पर फिनाइल, एसिटिक एसिड, पोटेशियम फिनाइल एसिडेट, बेन्जाइल सॉयनाइड तथा पेन्सीलीन के मूल्य बढ़ जाएंगे। अतः सोडियम सॉयनाइड से बनने वाले इन तैयार उत्पादों के उत्पादक उद्योगों को अलाभकारी होने के कारण अपनी ईकाइयों को बंद करना पड़ेगा। अतः अनुरोध यह है कि सोडियम सॉयनाइड जैसी पड़ने वाली मूल सामग्री के स्थान पर तैयार वस्तुओं जैसे पेन्सीलीन एवं उससे और आगे प्राप्त होने वाली वस्तुओं पर पाटन-रोधी-शुल्क लगाया जाए।

II. निर्यातकों के विचार

- (क) जर्मन संघीय गणराज्य (एफ आर जी) के निर्यातकों ने कहा है कि बाजार ढाँचे एवं भारतीय तथा स्वदेशी (यू. संघ) बाजार की अपेक्षाओं में मूलभूत भिन्नताओं व साथ ही क्वालिटी में भारी अन्तरों के कारण, दोनों बाजारों को अलग-अलग ही माना जा सकता है। उन्होंने क्षति के आरोपों से भी इंकार किया है क्योंकि, विश्व व्यापार संगठन देश औसत की तुलना में काफी ऊँचे आयात शुल्क के आधार पर भारतीय उत्पादकों की बाजार हिस्सेदारी का पहले ही उच्चतर होना, बाजार में उनके वर्चस्व को प्रमाणित करता है।
- (ख) जर्मन निर्यातक ने इस बात की ओर संकेत किया है कि स्वदेशी यूनिट बिक्री मूल्य और भारत में निर्यात यूनिट मूल्य में प्रधान अन्तर दोनों बाजारों के लिए पूर्णतः भिन्न लागत ढाँचे पर आधारित है। जर्मनी के लिए कार्पोरेट लागत, उत्पादन-बिक्री प्रशासनिक बंधा-खर्च और साथ ही पैकिंग लागत, भारत से अनुत्पन्नीय रूप से ऊँची है।
- (ग) उत्तर देने वाले कोरिया के निर्यातक ने कहा कि उनके द्वारा भारत में सोडियम सॉयनाइड के पाटन का मामला गुमराह करने वाला है क्योंकि उत्पादन की उनकी लागत, उनके स्वदेशी बिक्री मूल्य से कम है। इसके अतिरिक्त सोडियम सॉयनाइड के उनके निर्यात मूल्य, कोरिया में उनके स्वदेशी बाजार मूल्यों से अधिक हैं।

- (घ) कोरियाई निर्यातक मै० हैनवाह केमिकल कॉरपोरेशन, जिसने प्रश्नावली का उत्तर दिया है, ने कहा है कि भारतीय उत्पादकों की तुलना में उत्पादन की उनकी लागत, इस मूलभूत कारण से कम है कि सोडियम साँयनाइड हेतु उनकी उत्पादन सुविधा, उनके एक्रिलोनाइडाइल संयंत्र से प्राप्त, उप-उत्पादों को प्रयोग करते हुए, मूलतः एक अधो-प्रवाही परियोजना है। सोडियम साँयनाइड के उत्पादन में मुख्य कच्चा माल अर्थात् एचसीएन.गैस उन्हें एक्रिलोनाइडाइल उत्पादन से एक उप-उत्पाद के तौर पर प्राप्त होता है। इसके अलावा कॉस्टिक सोडा लाई, जिसके मूल्य विश्व बाजार में तेजी से गिरते रहे हैं, उनके संयंत्र को बगल में स्थित संयंत्र से एक पाइपलाइन द्वारा मिलती है। इन सब बातों से सोडियम साँयनाइड के उत्पादन की उनकी लागत काफी सीमा तक कम हो जाती है।
- (ङ) जर्मनी के निर्यातक ने अपने एवं वादी द्वारा उत्पादित सोडियम साँयनाइड हेतु विनिर्देशों एवं प्रसंस्करण में भिन्नताओं की ओर संकेत किया है। उनका दावा है कि उनका उत्पाद अधिकतम 0.005 प्रतिशत अघुलनशील उत्पाद अंश के साथ डीआईएनआईएसओ 50971 के अनुसार उत्पादित किया जाता है। भारतीय उत्पाद इस मानक के अनुसार नहीं है और इसमें अघुलनशील अंश दस गुना अधिक है। जर्मन निर्यातक के ग्राहक फर्मास्यूटिकल मध्यकों एवं अन्य उत्पादों के उत्पादन के विशेषज्ञ हैं, जिन्हें अपने उत्पादन के दौरान उच्च शुद्धता एवं अघुलनशील यौगिकों की अशुद्धताओं को न्यूनतम बनाए रखना पड़ता है। इसको देखते हुए, वे वादी के इस दावे को नहीं मानते कि उनके उत्पाद एवं आयातित उत्पाद में कोई महत्वपूर्ण अन्तर नहीं है तथा दोनों समान वस्तुएँ हैं और माल का आयात, पाटित मूल्यों पर उनकी उपलब्धता के कारण किया जाता है।
- (च) स्वदेशी यूरोपियन संघ बाजार के संबंध में यह कहा गया है कि विपणन प्रयास, भारतीय बाजार प्रयासों से स्पष्टतः भिन्न हैं। दूसरे के लिए अतिरिक्त लागतें बड़ी मात्रा वाले मध्यक कन्टेनरों में सोडियम साँयनाइड के भारी लागत वाले चार्ज एवं डिस्चार्ज, एक उच्च स्तरीय तकनीकी सलाह साँयनाइड विनाशक तकनीक और यूरोपियन संघ के कठोर वातावरणीय विनियमों के अनुपालन के कारण हैं।
- यूरोपीय संघ के प्रत्येक सदस्य की भिन्न विधिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए उन्होंने, सोडियम साँयनाइड के प्रयोग हेतु सुरक्षा अनुदेशों, प्रशिक्षण सत्रों एवं साँयनाइड गोदामों के सर्वेक्षण वाले विशेष रूप से बनाए कार्यक्रमों का विकास किया है।
- यूरोपियन संघ में उनका वितरण तंत्र काफी विस्तृत है तथा यूरोपियन संघ के अति विविधिकृत बाजार ढाँचे को सहायता एवं सप्लाई देने के लिए बिक्री कर्मचारियों और तकनीकी सेवाओं के बड़े दल की आवश्यकता है। अतः भारतीय बाजार से बिल्कुल विपरीत बिक्री लागत काफी अधिक है।
- (छ) पाटन के संबंध में, जर्मनी निर्यातकों ने, अवस्थापना, सप्लायर-खरीदार संबंध, अपने स्वदेशी बाजार की तकनीकी एवं पर्यावरणीय अपेक्षाओं को पूरा करने पर खर्च की जाने वाली राशि के संबंध में अपने स्वदेशी बाजार एवं भारतीय बाजार के बीच मूलभूत अन्तरों को प्रकाशित किया है। उनके अनुसार अपने-अपने बाजार की शर्तों एवं परिस्थितियों में अन्तरों को देखते हुए, भारतीय स्वदेशी बाजार के लागत ढाँचे एवं स्वदेशी बाजार वाले के बीच तुलना संभव न होने के कारण के आधार पर धारा 9-ए (1) (सी) के अंतर्गत पाटन का पता नहीं लगाया जा सकता।
- (ज) क्षति के संबंध में जर्मनी निर्यातक ने कहा है कि काफी ऊँचे आयात शुल्क आधार के कारण भारतीय उत्पादकों की बाजार हिस्सेदारी पहले ही बहुत अधिक है जो भारतीय बाजार में स्थानीय उत्पादकों के वर्चस्व का संकेतक है। जहां तक मूल्य का संबंध है, यह कहा गया है कि सोडियम साँयनाइड के दामों में विश्वभर में गिरावट आई है जैसाकि कैमिकल ट्रेड इण्डैलिजेंस, भारत के आँकड़ों से देखा जा सकता है। इण्डियन कैमिकल एक्सपोर्ट मूल्य-सूची में मार्च-दिसम्बर 1998 की अवधि के लिए अ. डा. 881/मी. टन का एफओबी मूल्य दिखाया गया है। एक अधिक विस्तृत निर्यात सूची से पता चलता है कि दूसरी ओर वादी ने अ. डा. 835 से अ. डा. 1000 तक के एफओबी मूल्यों पर निर्यात किया है। यह अ. डा. 890-1050 सी. आई. एफ./मी. टन से मेल खाता है और उस समय के विश्व बाजार मूल्यों से कम होता है।
- (झ) जर्मन निर्यातकों ने एशिया में नई उत्पादन सुविधाओं (अतिरिक्त क्षमता के लगभग 30000 टन/वर्ष) के साथ स्थिर एवं गिरती हुई माँग के कारण पिछले तीन वर्षों में विश्व बाजार मूल्यों में भारी गिरावट की ओर संकेत किया है। परिणामस्वरूप, कोई भी उत्पादन अपने मूल्यों को ऊँचा नहीं रख सका और उन्हें लागत कम करने वाले बड़े कार्यक्रमों को लागू करना पड़ा। तथापि, विश्व में गिरावट की प्रवृत्ति के बावजूद वादी ने केवल अपनी बिक्रियों की मात्रा बढ़ा सका, अपितु अपने स्वदेशी मूल्यों को भी बनाए रख सका जो कि सोडियम साँयनाइड के विश्व बाजार मूल्यों से 35.2 प्रतिशत अधिक है।
- (ञ) जर्मन निर्यातक एवं वादी के सोडियम साँयनाइड के विनिर्देशों एवं संसाधन के अन्तरों की तुलना करते हुए उत्तरवाती ने, वादी के उत्पादन की तुलना में उनके उत्पाद की महत्वपूर्ण क्वालिटी एवं पैकिंग लाभों की ओर संकेत किया है।

परिष्कृत तकनीकी एवं लॉजिस्टिकल अपेक्षाओं, जिनका यूरोपियन बाजार स्थानों में सोडियम साँयनाइड के सुरक्षित हैंडलिंग और सप्लाई की गारंटी देने के लिए होना अनिवार्य है, को पूरा करने के लिए लागत में क्वालिटी एवं पैकिंग पद्धतियाँ, आपातकालीन प्रतिक्रिया पद्धति, प्रतिक्रिया सम्भाल गतिविधियाँ; तथा नियंत्रण पद्धति साँयनाइड के इष्टतम उपयोग के लिए डिटॉकसीफिकेशन जैसी पेटेंट-शुदा टेक्नालॉजियाँ निर्यातकों के स्वदेशी विक्रय मूल्य का अभिन्न हिस्सा है। अतः निर्यातक का तर्क यह है कि उनके स्वदेशी बाजार (यू संघ) एवं भारतीय बाजारों की विशेषताओं में ऐसे मूलभूत अन्तर हैं कि स्वदेशी-बिक्री मूल्य के आधार पर सामान्य मूल्य का पता नहीं लगाया जा सकता। अतः उनका कहना है कि उनकी ओर से कोई पाटन नहीं है।

(ट) वादी को क्षति नहीं हुई है क्योंकि—

*भारतीय उत्पादकों की बाजार हिस्सेदारी बहुत ऊँची, 80 प्रतिशत से अधिक की है और पर्याप्त आयात शुल्क के आधार के कारण बाजार पर उनका वर्चस्व है।

*मूल्य के बारे में, विश्व बाजार मूल्यों में गिरावट है और इसका भारतीय बाजार पर भी प्रभाव पड़ा है।

*वादी के दावे के विपरीत उनके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अनुसार पिछले तीन वर्षों में स्वदेशी उद्योग में वादी की बिक्री की मात्रा 587 टन या 14 प्रतिशत की वृद्धि दिखाती है।

- (ठ) कारणात्मक संबंध के प्रश्न पर यह कहा गया है कि वादी के दावे के विपरीत, 1995-96 तथा 1998-99 के दौरान भारतीय बाजार की माँग में 833 टन या 11.94 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जबकि स्वदेशी उत्पादकों की बाजार हिस्सेदारी के प्रतिशत आँकड़ों में आंशिक 86.09 प्रतिशत से 81.87 प्रतिशत की गिरावट आई है, वास्तव में बेची गई मात्रा में 15.7 टनों की वृद्धि हुई है।

इसके अलावा यह भी कहा गया है कि इस बात के साक्ष्य हैं कि भारतीय उत्पादकों ने अपने निर्यात मूल्य उनके अर्थात् जर्मन निर्यातक द्वारा भारतीय बाजार में गारण्टी-शुदा मूल्यों से काफी नीचे पर एवं विश्व बाजार मूल्यों के निम्नतम पर दिए हैं। यह साक्ष्य इस तथ्य का विरोध करता है कि माल का भारत में पाटन किया जा रहा है। तथापि, वाद को आयातित माल से क्षति हुई है।

(घ) उठाए गए मुद्दों की जाँच

4. निर्यातकों, आयातकों, वादी एवं अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा किए गए पूर्वोक्त अभिवेदनों की जाँच की गई है, उन पर विचार किया है और इन निष्कर्षों में उन्हें उचित स्थानों पर लिया गया है।

(ङ) विचाराधीन उत्पाद

5. वर्तमान जाँच में संबंधित उत्पाद विषयगत देशों के मूल का या वहाँ से निर्यातित, सीमा शुल्क अधिनियम के सीमा-शुल्क उपशीर्ष 2837.11 के अन्तर्गत वर्गीकृत सोडियम सॉयनाइड है। यह वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और वर्तमान जाँच के कार्य-क्षेत्र पर किसी भी प्रकार से बाध्यकर नहीं है। सोडियम सॉयनाइड एक शुद्ध, मूल अकार्बनिक रसायन है। यह कार्बोनेट सोडा को हाइड्रोसोडियम एसिड (एचसीएन) की प्रतिक्रिया कर उत्पादित किया जाता है। यह मुख्यतः स्वर्ण अयस्क में से सोने को निकालने में प्रयुक्त होता है। फार्मास्यूटिकल्स तथा कीट-नाशक उद्योग भी इसे मध्यकों के तौर पर प्रयोग करते हैं। उद्योगों द्वारा यह रंजन मध्यक, इलैक्ट्रोप्लेटिंग रसायन जैसे उद्योगों एवं ताप उपचार-लवणों के उत्पादन हेतु भी प्रयोग किया जाता है।

(च) समान वस्तुएँ

6. वादी ने दावा किया है कि उनके उत्पाद एवं उक्त देशों से आयात किए गए उत्पाद में ऐसे कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं हैं जिनका मूल्य एवं क्वालिटी पर प्रभाव हो सकता है। दोनों, भौतिक एवं रसायनिक विशेषताओं (आकार रासायनिक संरचना), उत्पादन प्रक्रिया और तकनीक, कार्य एवं प्रयोगों, उत्पादन विनिर्देशों, वितरण एवं विपणन तथा माल के टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय हैं।

दोनों ही तकनीकी एवं वाणिज्यिक दृष्टि से स्थानापन्नीय हैं। आयातक, आयातित एवं स्वदेशी सोडियम सॉयनाइड को एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर रहे हैं। अतः ये दोनों पाटन-रोधी नियमावली के अर्थों में समान वस्तुएँ हैं। इस संबंध में, प्राधिकारी ने देखा है कि यद्यपि कुछ निर्यातकों ने प्रक्रिया, क्वालिटी एवं पैकिंग की दृष्टि से अपने उत्पाद और वादी के उत्पादन में अंतर का दावा किया है तथापि ये अंतर दोनों उत्पादों की समानता पर कोई प्रभाव नहीं डालते क्योंकि आयातकों एवं उपभोक्ताओं द्वारा दोनों का ही एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। प्राधिकारी पाता है कि दोनों के ही अन्त्यः प्रयोग एक ही हैं और दोनों की मूलभूत तकनीकी विशेषताएँ समान हैं। भारतीय उत्पाद की तुलना में आयातित उत्पाद की निम्नतर घातु संकेन्द्रन और जलीय अंश तथा साथ ही निम्नतर अघुलनीय मिश्रणों की दृष्टि से क्वालिटी की उत्तमता, दोनों की मूलभूत तकनीकी विशेषताओं में कोई अंतर नहीं डालती। अंतर केवल डिग्री में है, प्रकार में नहीं। इस प्रकार प्राधिकारी देखता है कि भारत में उत्पादित सोडियम सॉयनाइड, विषयगत देशों से आयातित सोडियम सॉयनाइड से बहुत मेल खाती हुई विशेषताओं वाला है। दोनों ही तकनीकी एवं वाणिज्यिक दृष्टि से स्थानापन्नीय हैं और पाटन-रोधी नियमावली के अर्थों के भीतर समान वस्तु माने गए हैं।

(छ) स्वदेशी उद्योग

7. याचिका, मै. सॉयनाइड्स एंड कैमिकल्स कम्पनी, 65 फ्री प्रैस हाउस, नारीमन प्वाइंट, मुम्बई द्वारा दायर की गई है। भारत में सोडियम सॉयनाइड का केवल एक और उत्पादक अर्थात् मै. गुजरात अल्कलीज एण्ड कैमिकल्स लि. है। जाँच अवधि के दौरान भारत में सोडियम सॉयनाइड का कुल उत्पादन 5628 मी. टन था जिसमें से वादी ने 4413 मी. टन सोडियम सॉयनाइड का उत्पादन किया था। इस प्रकार वादी का सोडियम सॉयनाइड का उत्पादन, स्वदेशी उत्पादन के 25 प्रतिशत से अधिक का होता है, अतः प्राधिकारी नोट करता है कि उनके (वादी) पास नियमावली के अंतर्गत स्वदेशी उद्योग की ओर से याचिका दायर करने का अपेक्षित आधार है।

(ज) पाटन

8. किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य धारा 9 ए (1)(ग) के अंतर्गत निम्नलिखित अर्थ रखता है —

- (i) व्यापार के सामान्य व्यवहार में समान वस्तुओं के लिए उपधारा (6) के अंतर्गत बने नियमों के अनुसार यथानिश्चित तुलनात्मक मूल्य जबकि ऐसी वस्तु निर्यातक देश या क्षेत्र में उपयोग के लिए आश्रित हो; या
- (ii) जहां निर्यातक देश या क्षेत्र के स्वदेशी बाजार में व्यापार के सामान्य व्यवहार में समान वस्तु की कोई बिक्री नहीं हो या विशेष बाजार दशा के कारण अथवा निर्यातक देश या क्षेत्र के स्वदेशी बाजार में बिक्रियों की कम मात्रा के कारण, ऐसी बिक्रियों की वजह से तुलना नहीं हो सकती हो तो सामान्य मूल्य या तो —

(क) निर्यातक देश या क्षेत्र से आयात किये जाने पर समान वस्तु की उपधारा (6) के अंतर्गत बने नियमों के अनुसार यथानिश्चित तुलनात्मक प्रतिनिधि मूल्य या उचित तीसरे देश का तुलनात्मक प्रतिनिधि मूल्य, या

(ख) उपधारा (6) के अंतर्गत बने नियमों के अनुसार यथानिश्चित, प्रशासनिक बिक्री और सामान्य लागतों एवं लाभों के लिए उचित वृद्धि के साथ मूल्य के देश में उक्त वस्तु के उत्पादन की लागत;

बशर्ते कि मूल्य के देश के अलावा अन्य किसी देश से वस्तु के आयात के मामले में या जहां वस्तु निर्यात के देश से केवल गुजरी हो या ऐसी वस्तु निर्यात के देश में उत्पादित नहीं होती हो या निर्यात के देश में उसका कोई तुलनात्मक मूल्य नहीं हो, तो इसके सामान्य मूल्य का निर्धारण, मूल्य के देश में इसके मूल्य के संदर्भ में किया जाएगा।

9. प्राधिकारी ने ऊपर दी गई धारा के अनुसार विषयगत देशों के निर्यातकों को प्रश्नावली भेजी। निर्यातकों द्वारा सामान्य मूल्य एवं निर्यात मूल्य के बारे में किए गए दावे निम्नलिखित हैं —

(झ) सामान्य मूल्य एवं निर्यात मूल्य पर निर्यातकों के दावे

10. क. ई यू

निर्यातक: पी सी के राफ़ीनरी जी एम बी एच

निर्यातक ने दावा किया है कि उन्होंने विशिष्ट अवधि, अर्थात् 1 अप्रैल, 1998 से 31 दिसम्बर, 1998 तक के दौरान भारत को सोडियम सॉयनाइड का कोई निर्यात नहीं किया है और यह कि 30 जून, 1998 से उनका उत्पादन बंद हो गया है। वे प्रश्नावली को भरना जरूरी नहीं समझते।

निर्यातक: ई मर्क

निर्यातक का कहना है कि उन्होंने भारत के किसी भी भाग के लिए सोडियम सॉयनाइड के न तो बीजक बनाए और ना ही निर्यात किए। अतः वे प्रश्नावली नहीं भरेंगे।

निर्यातक: मै. देगुस्सा हल्स

निर्यातक ने स्वदेशी मूल्य एवं भारत को निर्यात मूल्य के संबंध में सोडियम सॉयनाइड हेतु सूचना दी है।

सामान्य मूल्य

निर्यातक ने समस्त यूरोपियन संघ (यू.सं. को स्वदेशी बाजार माना गया है) में, स्वदेशी बिक्री के संबंध में भारत औसत बिक्री मूल्य के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया और उस पर समायोजन माँगा है। समायोजन, कमीशन, बीमे, ब्याज तथा भाड़े के लिए माँगा गया है। इस प्रकार माँगा गया सामान्य मूल्य, अर्थात् फैक्ट्री स्तर पर स्वदेशी बिक्री मूल्य अ. डा. ****/मी. टन का माँगा गया है।

निर्यात मूल्य

भारत को निर्यात मूल्य का दावा, जाँच अवधि के दौरान भारत को किए गए निर्यातों के भारत औसत सीआईएफ मूल्य के आधार पर किया गया है। समायोजनों की माँग कमीशन, एफओबी लागत, ब्याज, समुद्री भाड़े और बीमे के लिए की गई हैं। तदनुसार फैक्ट्री स्तर पर निर्यात मूल्य अ. डा. ****/मी. टन का माँगा गया है।

यूरोपीय संघ के शिष्टमंडल और ईयू के दूसरे निर्यातकों [उपर्युक्त पैराग्राफ* (ख) में उल्लिखित नामों से हतर] ने अपने सदस्य देशों के निर्यातकों द्वारा निर्यातित संबद्ध माल के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य की सूचना नहीं दी है जो पाटन और पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए आवश्यक है। इसलिए प्राधिकारी इस संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा मुहैया कराई गई सूचना पर विचार करते हैं।

(ख) देश: कोरिया गणराज्य

उत्पादक: तोंग सूह पैट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लि.

निर्यातक: हन्हा एण्ड कैमिकल्स कारपोरेशन लि.

निर्यातक ने स्वदेशी एवं निर्यात मूल्य के संबंध में सूचना दी है।

सामान्य मूल्य

निर्यातक ने, जाँच अवधि के दौरान स्वदेशी बिक्रियों के औसत बिक्री मूल्य के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया है और उस पर समायोजन मांगे हैं। समायोजनों की मांग स्थानीय परिवहन, बीमा, मूल्य सम्बद्धित कर और एजेन्सी के कमीशन हेतु की गई है। स्वदेशी बिक्री मूल्य के प्रमाण के रूप में निर्यातक ने दो स्वदेशी बीजकों की प्रतियाँ भेजी हैं। संबंधित अवधि हेतु बिक्री मूल्य अ. डा. ****/मी. टन माँगा गया है। इस पर माँगे गए समायोजन को लेते हुए सामान्य मूल्य अ. डा. *****/मी. टन माँगा गया है।

निर्यात मूल्य

यहां पर भारत के लिए औसत निर्यात मूल्य (सीआईएफ) अ. डा./मी. टन माँगा गया है और कोरिया में स्थानीय परिवहन (फैक्ट्री से बन्दरगाह तक), भारत को समुद्री भाड़े, बीमे, कण्टेनर कर हैण्डलिंग प्रभार और एजेन्टों के लिए मार्जिन हेतु समायोजन मांगे गए हैं। इस प्रकार फैक्ट्री स्तर पर निर्यात मूल्य अ. डा. *****/मी. टन माँगा गया है।

(ग) देश : अमरीका

निर्यातक : स्टर्लिंग कैमिकल्स

उत्पादक/निर्यातक ने कहा है कि वे वर्तमान जांच में एक सही पार्टी नहीं हैं। उनका कहना है कि वे ईआईडूपोन्ट के स्वामित्व में हैं और वे केवल विपणन माल बनाते हैं। वे अपने द्वारा उत्पादित सोडियम सॉयनाइड की बिक्री, निर्यात या किसी भी प्रकार से विपणन नहीं करते हैं। इस प्रकार उनका कहना है कि वे जाँच में सही पार्टी नहीं हैं।

देश: अमरीका

निर्यातक/उत्पादक: सी.पी. कैमिकल्स

यह कहा गया है कि सी.पी. कैमिकल्स ने संबंधित अवधि, 1 अप्रैल, 1998 से 31 दिसम्बर, 1998 के पहले कभी भी, इसके दौरान या इसके बाद में, सोडियम सॉयनाइड का न तो उत्पादन किया है और न ही निर्यात।

इस प्रकार प्राधिकारी ने पाया है कि अमरीका से किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने न तो प्रश्नावली का उत्तर दिया है और न ही सामान्य मूल्य एवं निर्यात मूल्य के संबंध में अपेक्षित सूचना दी है। अतः प्राधिकारी, वादी द्वारा दी गई सूचना एवं डीजीसीआईएस से प्राप्त निर्यात मूल्य को ही सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना मानता है।

(घ) देश: चेक गणराज्य

चेक गणराज्य से किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने सामान्य मूल्य एवं निर्यात मूल्य के संबंध में अपेक्षित सूचना नहीं दी है। अतः इन पर वादी की सूचना एवं डीजीसीआईएस स्रोतों से प्राप्त निर्यात मूल्य को प्राधिकारी ने लिया है तथा तदनुसार प्राधिकारी, सामान्य मूल्य एवं निर्यात मूल्य का निर्धारण करता है।

(ज) निर्यातकों द्वारा किए गए दावों की प्राधिकारी द्वारा जांच

- II. सामान्य मूल्य एवं निर्यात मूल्य के बारे में सूचना देने वाले विभिन्न निर्यातकों के दावों की निम्नलिखित के अनुसार जांच की जाती है:

(क) देश: अमरीका

यद्यपि अमरीका के दो उत्पादकों/निर्यातकों ने उत्तर दिए हैं, किन्तु प्राधिकारी नोट करता है कि किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने विद्यमान उद्पाद के सामान्य मूल्य एवं निर्यात मूल्य के संबंध में सूचना नहीं दी है। अतः प्राधिकारी, वादी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना एवं डीजीसीआईएस स्रोत से प्राप्त निर्यात मूल्य को सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना मानता है और सामान्य मूल्य एवं निर्यात मूल्य क्रमशः अ. डा. 1450/मी. टन तथा अ. डा. 760/मी. टन निश्चित करता है। इस प्रकार पाटन-मार्जिन अ. डा. 690/मी. टन आकलित किया जाता है जो निर्यात मूल्य का 90.78 प्रतिशत है।

(ख) देश: ई यू

निर्यातक: मै. देगुस्सा हल्स

यहां प्राधिकारी नोट करता है कि निर्यातक ने सामान्य मूल्य का दावा, यूरोपियन संघ, जो निर्यातक द्वारा समग्र रूप में स्वदेशी बाजार माना जाता है के विभिन्न सदस्य देशों में उनकी बिक्रियों के भारित औसत स्वदेशी मूल्य के आधार पर किया जाता है। प्राधिकारी, निर्यातक द्वारा कमीशन, बीमे, ब्याज एवं भाड़े के लिए मांगे गए समायोजन को स्वीकार करता है। इस प्रकार प्राधिकारी, सत्यापन के अधीन रहते हुए, आरम्भिक निष्कर्षों के लिए अ. डा. ****/मी. टन के सामान्य मूल्य को निश्चित करता है।

निर्यात मूल्य के बारे में, प्राधिकारी नोट करता है कि निर्यातक का उसके लिए किया गया दावा, भारत के निर्यातों के भारित औसत सीआईएफ मूल्य के आधार पर है। प्राधिकारी ने कमीशन, एफओबी लागत, ब्याज, समुद्री भाड़े और बीमे के लिए मांगे गए समायोजनों की अनुमति दे दी है। इस प्रकार प्राधिकारी, सत्यापन के अधीन रहते हुए निर्यात मूल्य अ. डा./मी. टन तय करता है। पाटन मार्जिन का हिसाब अ. डा. 356.45/मी. टन का बनता है जो निर्यात मूल्य का 37 प्रतिशत है।

प्राधिकारी नोट करता है कि न ही ई यू सदस्य राष्ट्रों (उपयुक्त पैराग्राफ क. 1. *III में उल्लिखित नामों से इतर) के निर्यातकों/उत्पादकों ने और न ही यूरोपीय संघ के शिष्टमण्डल ने प्रश्नावली का उत्तर दिया है। इस प्रकार उन्होंने सोडियम सायनाइड के सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य के संबंध में सूचना नहीं दी है। इसलिए यूरोपीय संघ के सभी असहयोगी निर्यातकों के संबंध में सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य तथा पाटन मार्जिन याचिकाकर्ता द्वारा मुहैया कराई गई सूचना पर आधारित है।

प्राधिकारी ने कहा है कि एफआरजी और यूरोपीय संघ के खिलाफ याचिकाकर्ता के अनुरोध पर मामला शुरू करते समय एफआरजी को यूरोपीय संघ का एक हिस्सा और दूसरे को एक व्यापार एवं टैरिफ अवरोधों से मुक्त क्षेत्र मानते हुए मामले की जाँच यूरोपीय संघ के सभी निर्यातकों के संबंध में एक क्षेत्र के रूप में की गई है।

(ग) देश: चेक गणराज्य

प्राधिकारी नोट करता है कि किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने विचाराधीन उत्पाद के सामान्य मूल्य एवं निर्यात मूल्य के बारे में अपेक्षित सूचना नहीं दी है। अतः प्राधिकारी, वादी द्वारा दी गई सूचना एवं डीजीसीआई स्रोत से प्राप्त निर्यात मूल्य (सीआईएफ) को सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना मानता है और सामान्य मूल्य एवं निर्यात मूल्य क्रमशः अ. डा. 1581/मी. टन व अ. डा. 912 मी. टन निश्चित करता है।

इस प्रकार पाटन मार्जिन अ. डा. 669/मी. टन निश्चित किया जाता है जो निर्यात मूल्य का 73.35 प्रतिशत है।

(घ) देश: कोरिया गणराज्य

निर्यातक: मै० हन्हा कैमिकल कार्पोरेशन

उत्पादक: मै० टोंग सुह पैट्रोकेमिकल कार्पोरेशन लि०

प्राधिकारी नोट करता है कि वादी ने औसत स्वदेशी बिक्री मूल्य के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया तथा स्थानीय परिवहन, बीमे, मूल्य संवर्द्धन कर एवं एजेन्सी कमीशन हेतु समायोजनों की माँग की है। प्राधिकारी ने समायोजनों की अनुमति दे दी है। प्राधिकारी यह भी नोट करता है कि स्वदेशी बिक्री मूल्य के साक्ष्य के तौर पर निर्यातक ने जाँच अवधि से संबंधित घरेलू बीजकों की प्रतियाँ दी हैं। प्राधिकारी यह भी नोट करता है कि इस मामले में सोडियम सायनाइड का उत्पादन, उत्पादक के दूसरे संयंत्र के उप-उत्पाद को सोडियम सायनाइड हेतु कच्चे माल के तौर पर प्रयोग करते हुए एक अधो-प्रवाही प्रक्रिया है। इसमें उत्पादन की लागत भी कम हो जाती है। अतः प्राधिकारी सत्यापन के अधीन रहते हुए आरंभिक निश्चयन के प्रयोजन के लिए अ.डा. $\times\times\times\times\times$ /मी. टन का सामान्य मूल्य निश्चित करता है।

निर्यात मूल्य का दावा भारत के लिए भारित औसत निर्यात मूल्य के आधार पर किया गया है जिसे प्राधिकारी डी जी सी आई एंड एस के आंकड़ों के अनुरूप पाता है। समायोजनों का दावा कोरिया में स्थानीय भाड़े, भारत के लिए समुद्री भाड़े, बीमा, कंटेनर कर और हैंडलिंग प्रभार तथा कमीशन के कारण किया गया है। प्राधिकारी द्वारा सत्यापन के अधीन रहते हुए, आरंभिक निर्धारण के प्रयोजनार्थ दावा किए गए इन खर्चों की अनुमति दी जाती है। इस प्रकार निर्यात मूल्य सत्यापन के अधीन रहते हुए $\times\times\times\times\times$ अ.डा./मी. टन निर्धारित किया जाता है। प्राधिकारी यह पाते हैं कि इस प्रकार से निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य की तुलना से पाटन मार्जिन शून्य प्रदर्शित होता है।

असहयोगी निर्यातक:—

विषयगत देशों के उन अ-सहयोगी निर्यातकों के बारे में जिन्होंने प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है, प्राधिकारी पाटन मार्जिन को सामान्य मूल्य एवं निर्यात मूल्य पर उनकी (वादी की) सूचना के आधार पर समग्र रूप से संबंधित देश/क्षेत्र हेतु वादी द्वारा माँगे गए के अनुसार निश्चित करता है। इस प्रकार विषयगत देशों/क्षेत्रों एवं निर्यातकों के संबंध में कैकट्टी स्तर पर निर्यात मूल्य के प्रतिशत के तौर पर पाटन-मार्जिन, निम्नलिखित के अनुसार निश्चित किया जाता है:

	देश	निर्यातक	पाटन-मार्जिन
1.	अमरीका	सभी निर्यातक	98.78 %
2.	ईयू	(i) मै० देगुस्सा हल्स	37 %
		(ii) सभी अन्य निर्यातक	54 %
3.	चेक गणराज्य	सभी निर्यातक	73.35 %
4.	कोरिया गणराज्य	(i) मै० हन्हा कैमिकल कार्पोरेशन लि० तथा मै० टोंग सुह पैट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन	शून्य
		अन्य निर्यातक	89.20 %

ट. क्षति

12. पूर्वोक्त नियम 11 अनुलग्नक-II के अंतर्गत जब क्षति का निष्कर्ष निकाला जाता है तो निष्कर्ष में घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति का निर्धारण भी शामिल होगा, "ऐसा करते समय सभी संयोजित तथ्यों को ध्यान में रखा जाएगा जिनमें पाटित आयातों की मात्रा, स्वदेशी बाजार में समान वस्तुओं के मूल्यों पर उनका प्रभाव तथा ऐसी वस्तुओं के स्वदेशी उत्पादों पर ऐसे आयातों का परिणामी प्रभाव शामिल होगा।" मूल्यों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते हुए, इस बात की जाँच करना आवश्यक समझा गया है कि क्या भारत में समान उत्पाद के मूल्य की तुलना में पाटित आयातों द्वारा मूल्यों में पर्याप्त कटौती की गयी है या ऐसे आयातों का प्रभाव पर्याप्त मात्रा में मूल्यों को अन्यथा कम करना या मूल्यों में होने वाली वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा काफी बढ़ गए होते।

पूर्वोक्त नियम 11 के अनुलग्नक II (iii) के अनुसार जब एक से अधिक देशों से उत्पाद के आयात पाटन रोधी जाँच के अधीन होते हैं तो नाम-निर्दिष्ट अधिकारी, ऐसे आयातों के संचयित प्रभाव का आकलन तभी करेगा जबकि यह निश्चित हो कि प्रत्येक देश से निर्यातों के संबंध में पाटन का मार्जिन, निर्यात मूल्य के प्रतिशत के तौर पर व्यक्त किये जाने पर 2 प्रतिशत से अधिक तथा प्रत्येक देश से किये गए आयात की मात्रा, भारत में समान वस्तु के आयात का 3 प्रतिशत है या जहाँ अलग-अलग देश के निर्यात 3 प्रतिशत से कम है, और समान संचयित आयात समान वस्तु के आयातों के 7 प्रतिशत से अधिक है और आयातों का प्रभाव, आयातित वस्तु एवं समान स्वदेशी वस्तुओं के बीच प्रतिस्पर्धा की दशाओं के प्रकाश में उचित है।

प्राधिकारी नोट करता है कि पाटन का मार्जिन तथा संयुक्त देश से आयातों की मात्रा, उपरोक्त निर्धारित सीमाओं से अधिक है। आयातों के प्रभाव का संचयित आकलन उचित है क्योंकि विपयगत देशों के निर्यात मूल्य भारतीय बाजार में स्वदेशी उद्योग द्वारा दिए गए मूल्यों के साथ सीधी प्रतिस्पर्धा कर रहे थे।

भारत में स्वदेशी उद्योग पर आयातों के प्रभाव की जाँच करने के लिए प्राधिकारी ने, पूर्वोक्त नियमावली के अनुलग्नक-II (iv) के अनुसार ऐसे और संकेतकों पर विचार किया है जो उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डाल सकते हैं जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, विक्री की मात्रा, लाभकारिता, शुद्ध विक्री प्राप्त और पाटन की सघनता और मार्जिन आदि।

(क) आयात की मात्रा

प्राधिकारी ने इस संबंध में वादी के एवं डी जी सी आई एम, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित आँकड़ों पर विचार किया है तथा पाया है कि दोनों के बीच आंशिक अंतर है। तथापि, प्राधिकारी ने विपयगत देशों से आयात रुझान एवं इसके कारण स्वदेशी उद्योग को हुई क्षति का विश्लेषण करने के लिए सरकारी निकाय, डी जी सी आई एस, कलकत्ता द्वारा यथा प्रकाशित, आयात की मात्रा के आँकड़ों पर भरोसा किया है।

डी जी सी आई एण्ड एम द्वारा प्रकाशित आँकड़ों के यथानुसार पिछले तीन वर्षों एवं जाँच अवधि के दौरान आयातों की मात्रा निम्नलिखित के अनुसार है:

	1995-96	1996-97	1997-98	(मी. टन) जाँच अवधि (वार्षिक)
—विपयगत देशों से	890	1210	1393	1245(1660)
—अन्यों से	148	304	371	100(133)
—कुल	1038	1514	1764	1345(1793)

उपरोक्त आँकड़ों से यह देखा गया है कि (क) 1995-96 की तुलना में जाँच अवधि के दौरान (वार्षिकीय आधार पर) विपयगत देशों से कुल आयातों की मात्रा में वास्तविक रूप में 86.5% की वृद्धि हुई है, (ख) विपयगत देशों से आयातों की मात्रा वर्ष 1995-96, 1996-97, 1997-98 एवं जाँच अवधि के मूल आयातों का क्रमशः 85%, 80%, 79% तथा 93% रही है।

(ख) उत्पादन क्षमता एवं उपयोग :

वादी ने कहा है कि उनकी संस्थापित क्षमता 6372 मी. टन की है जो पिछले वर्षों में नहीं बदली है। वर्षों के दौरान उत्पादन में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है। क्षमता उपयोग 1995-96 में 89.78%, 1996-97 में 87.29%, 1997-98 में 86.94% तथा जाँच अवधि के दौरान 92.34% रहा है।

(ग) बिक्री की मात्रा एवं बाजार हिस्सेदारी :

स्वदेशी उद्योग की बिक्री की मात्रा जो 1995-96 में 4201 मी. टन थी जाँच अवधि के दौरान (वार्षिकीय आधार पर) बढ़ कर 4761 मी. टन हो गई। स्वदेशी उद्योग की बाजार हिस्सेदारी, जो 1996-97 में 74.3% थी, 1997-98 में बढ़ कर 79.5% हो गई और जाँच अवधि के दौरान घट कर 72.35% हो गई।

(घ) रोजगार :

यह देखा गया है कि खादी के यहाँ नियुक्त जनशक्ति में गिरावट आई है जो 1996-97 में 334 थी किन्तु 1998-99 में घट कर 317 हो गई।

(ङ) औसत बिक्री प्राप्तियाँ एवं लाभकारिता

वर्ष 1995-96 के दौरान औसत बिक्री प्राप्तियाँ रु०...../ मी. टन, 1996-97 में रु०...../ मी. टन और 1997-98 में रु०...../मी. टन थीं। यह 1996-97 में के रु०...../मी. टन से घट कर 1997-98 में रु०...../मी० टन की रह गई। जाँच अवधि के दौरान, यह देखा गया है कि औसत बिक्री प्राप्ति और गिर कर रु०...../मी.टन हो गया। यह देखा गया है कि खादी ने 1997-98 तथा जाँच अवधि के दौरान हानि उठाई है और प्रति मीटरिक टन हानि 1997-98 के रु०...../ मी. टन से बढ़ कर जाँच अवधि अर्थात् अप्रैल-दिसम्बर 1998 में रु०...../मी. टन हो गई।

ख. क्षति पर निष्कर्ष

13. क्षति मापकों पर उपरोक्त विचारों के प्रकाश में निम्नलिखित निष्कर्ष निकले हैं:

- (क) 1995-96 की तुलना में, जाँच अवधि के दौरान विषयगत देशों से आयातों की मात्रा एवं कुल आयातों में वृद्धि हुई है।
जाँच अवधि के दौरान विषयगत देशों से आयातों की बाजार हिस्सेदारी 1996-97 के दौरान 21.54% से बढ़कर 25.32% हो गई।
- (ख) उत्पादन एवं क्षमता उपयोग, वर्षों के दौरान स्थिर रहा है।
- (ग) खादी के कर्मचारियों की संख्या में आंशिक कमी आई है।
- (घ) वर्ष 1995-96 की तुलना में, जाँच अवधि के लिए खादी की बिक्रियों की वास्तविक मात्रा उच्चतर थी। तथापि, विषयगत देशों से आयातों में वृद्धि के कारण, पिछले वर्ष की तुलना में, जाँच अवधि के दौरान खादी की बाजार हिस्सेदारी कम हुई है।
- (ङ) वर्ष 1997-98 के पिछले साल में, जाँच अवधि की तुलना में, विषयगत माल के औसत बिक्री मूल्य में गिरावट आई है। इसके परिणामस्वरूप खादी को जाँच अवधि के दौरान हानि हुई है।

उपरोक्त सभी कारक अर्थात् विषयगत देशों से आयातों की मात्रा में वृद्धि बाजार हिस्सेदारी में गिरावट, रोजगार में कमी, औसत बिक्री प्राप्तियों में गिरावट हुई। शून्य में वृद्धि यह बताते हैं कि स्वदेशी उद्योग को आर्थिक क्षति हुई है।

ड. कारणात्मक संबंधः

14. यह स्थापित करने में कि विषयगत देशों से आयातों के कारण आर्थिक क्षति हुई है प्राधिकारी का मानना है कि विषयगत देशों से आयातों की मात्रा में वृद्धि के परिणामस्वरूप खादी की बाजार हिस्सेदारी में गिरावट आई है। इसका प्रभाव स्वदेशी उत्पाद के मूल्यों में अंडरकटिंग रहा है जिससे स्वदेशी उद्योग को अपने उचित बिक्री मूल्य से नीचे पर बिक्री करनी पड़ी है। परिणामतः, स्वदेशी उद्योग अपने उचित बिक्री मूल्य प्राप्त नहीं कर सका और इसलिए उसे हानि हुई थी। अतः विषयगत देशों से हुए पाटित आयातों के कारण स्वदेशी उद्योग को आर्थिक क्षति हुई थी।

ब. भारतीय उद्योग का हित एवं अन्य मुद्दे

15. पाटनरोधी सीमा-शुल्कों का प्रयोजन सामान्यतया उस पाटन को खत्म करना है जो स्वदेशी उद्योग को क्षति पहुंचा रहा है और भारतीय बाजार में एक मुक्त एवं उचित प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को पुनःस्थापित करना है जो देश के सामान्य हित में है।

16. यह मानी हुई बात है कि पाटन-रोधी सीमा-शुल्क का लगाया जाना, विषयगत माल का प्रयोग करते हुए बने उत्पादों के मूल्य स्तरों को प्रभावित कर सकता है और फलस्वरूप इन उत्पादों की संबंधित प्रतिस्पर्द्धिता पर कुछ प्रभाव डाल सकता है। तथापि, भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्द्धा, पाटन रोधी उपायों से कम नहीं होगी, विशेषरूप से जबकि पाटन-रोधी सीमा-शुल्क की लेवी को उस राशि तक प्रतिबंधित रखा जाता है जहां तक स्वदेशी उद्योग को हुई क्षति की पूर्ति होती है। इसके विपरीत पाटन-रोधी उपाय लगाने से पाटनरोधी चलनों से प्राप्त होने वाले अनुचित लाभों को रोका जा सकेगा, इससे स्वदेशी उद्योग की गिरावट रूकेगी और सोडियम सायनाइड को उपभोक्ताओं के अधिक किस्में उपलब्ध करने में सहायता मिलेगी। पाटन-रोधी उपाय लगाना किसी भी प्रकार से विषयगत देशों से आयातों को नहीं रोकेगा और इसलिए उपभोक्ताओं को उत्पाद की उपलब्धता को प्रभावित नहीं करेगा।

17. स्वदेशी उद्योग की क्षति को समाप्त करने के लिए आवश्यक पाटन-रोधी सीमा-शुल्क का पता लगाने हेतु प्राधिकारी, स्वदेशी उद्योग के लिए क्षमता उपयोग के ईष्टतम स्तर पर उत्पादन की ईष्टतम लागत को लेते हुए स्वदेशी उद्योग हेतु, भारत में सोडियम सायनाइड के उचित बिक्री मूल्य पर भरोसा कर सकता है।

ण. निष्कर्ष

18. पूर्वोक्त पर विचार करने के बाद यह देखा गया है कि :

(क) कोरिया गणराज्य के मै. हन्वाह कैमिकल्स कारपोरेशन एवं मै. डांग सूह पेट्रोकेमिकल्स लिमि. मूल के या वहां से निर्यातित के सिवाय, चेक गणराज्य अमरीका, कोरिया गणराज्य एवं यूरोपीय संघ मूल के या वहां से निर्यातित तथा पैरा 5 में वर्णित सोडियम सायनाइड, सामान्य मूल्य से नीचे के मूल्य पर निर्यात किया गया है जिसके परिणामस्वरूप पाटन हुआ है।

(ख) भारतीय उद्योग को आर्थिक क्षति हुई है।

(ग) विषयगत देशों से पाटित आयातों से संचयित क्षति हुई है।

19. विषयगत देशों के मूल के या वहां से निर्यातित सोडियम सायनाइड के सभी आयातों पर अंतिम निश्चयन होने तक, अनन्तिम तौर पर पाटन-रोधी सीमा-शुल्क लगाना आवश्यक समझा जाता है।

20. प्राधिकारी ने पाटन मार्जिन के बराबर या उससे कम पाटन-रोधी शुल्क की सिफारिश करने पर विचार किया जिसकी यदि उगाही की जाएगी तो वह घरेलू उद्योग की क्षति को समाप्त कर देगी। इस प्रयोजन के लिए आयातों के लैण्डिड मूल्य की तुलना, जांच अवधि के लिए निश्चित वादी के क्षति रहित बिक्री मूल्य के साथ की गई थी। जहां कहीं भी अंतर पाटन-मार्जिन से कम था, वहां पाटन-मार्जिन से कम शुल्क की सिफारिश की जाती है। तदनुसार प्रस्ताव है कि अंतिम निश्चयन होने तक सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम के सीमा-शुल्क उप शीर्ष सं. 2837.11 के अंतर्गत आने वाले अमरीका, जर्मन जनवादी गणराज्य, चेक गणराज्य, कोरिया गणराज्य और यूरोपियन संघ के मूल के या वहां से निर्यातित सभी सोडियम सायनाइडों पर इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए जाने वाली अधिसूचना की तारीख से, अनन्तिम पाटन-रोधी शुल्क लगाया जाए।

21. विषय देशों/क्षेत्र एवं निर्यातकों के संबंध में पाटन-रोधी शुल्क निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ 4 में दी गई राशियां होंगी :—

क्रम सं.	देश	निर्यातक	राशि (रु. प्रति मी. टन)
1.	अमरीका	सभी निर्यातक	401
2.	ई. यू.	1. मै. देगुम्सा हल्स	कोई शुल्क नहीं
		2. अन्य सभी निर्यातक	3339
3.	चेक गणराज्य	सभी निर्यातक	2470
4.	कोरिया गणराज्य	1. मै. हन्वाह कैमिकल्स कारपोरेशन तथा	कोई शुल्क नहीं
		2. मै. ठोंगसु पेट्रोकेमिकल्स कार्पो. लिमिटेड	कोई शुल्क नहीं
		3. सभी अन्य निर्यातक	11460

22. प्रयोजन के लिए लैण्डिड मूल्य सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3, 3ए, 8बी, 9 तथा 9ए के अधीन लगाए गए शुल्कों को छोड़कर सीमा-शुल्क अधिनियम 1962 के अंतर्गत सीमा शुल्क द्वारा यथा निश्चित समाकलन योग्य मूल्य होगा और उसमें सभी सीमा-शुल्क शामिल होंगे।

(त) भावी पद्धति

23. प्रारंभिक निष्कर्षों को अधिमूचित करने के पश्चात् निम्नलिखित पद्धति अपनाई जाएगी :

(क) प्राधिकारी इन निष्कर्षों पर सभी हितबद्ध पार्टियों से टिप्पणियां मांगेगा और अंतिम निष्कर्षों में उन पर विचार किया जाएगा;

(ख) निर्यातकों, आयातकों, वादियों तथा अन्य ज्ञात हितबद्ध पार्टियों को प्राधिकारी द्वारा अलग से लिखा जा रहा है जो इस अधिसूचना के प्रेषण के चालीस दिनों के भीतर अपने विचार बता सकते हैं। अन्य कोई हितबद्ध पार्टी भी, इन निष्कर्षों के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों के भीतर अपने विचार दे सकती है।

(ग) अंतिम निष्कर्षों को घोषित करने से पहले प्राधिकारी आवश्यक तथ्यों को उद्घाटित करेगा।

रति विनय झा, नाम-निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE**NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th October, 1999

Preliminary Findings

Subject :—Anti-dumping investigation concerning imports of Sodium Cyanide from United States of America, Federal Republic of Germany (FRG), Czech Republic, Korea R P and the Territory of European Union—Preliminary Findings.

No. 8/1/99-DGAD.— Having regard to the Customs Tariff Act 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, thereof;

A. PROCEDURE

1. The procedure described below has been followed with regard to the investigation:
 - i. The Designated Authority (hereinafter also referred to as Authority), under the above Rules, received a written application from M/s Cyanides and Chemicals Co. on behalf of the domestic industry, alleging dumping of Sodium Cyanides (hereinafter also referred to as subject goods) originating in or exported from United States of America, Federal Republic of Germany (FRG), Czech Republic, Korea R P and the Territory of European Union.
 - ii. Preliminary scrutiny of the application filed by petitioner revealed certain deficiencies, which were subsequently rectified by the petitioner. The petition was therefore considered as properly documented;

- iii. The Authority, on the basis of sufficient evidence submitted by the petitioner decided to initiate the investigation against imports of Sodium Cyanides from United States of America, Federal Republic of Germany, Czech Republic, Korea R P and the Territory of European Union.
- iv. The Authority notified the Embassy of USA, Federal Republic of Germany, Czech Republic, Korea RP and the Territory of European Union about the receipt of dumping allegation before proceeding to initiate the investigation in accordance with sub-rule 5(5) of the Rules;
- v. The Authority issued a public notice dated 8th March, 1999 published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating anti - dumping investigations concerning imports of Sodium Cyanide classified under custom sub-heading No. 2837.11.00 of the Customs Tariff Act, 1975 originating in or exported from USA, Federal Republic of Germany, Czech Republic, Korea RP and the Territory of European Union (hereinafter also referred to as the subject countries).
- vi. The Authority forwarded a copy of the public notice to all the known exporters (whose details were made available by the petitioner) of the subject goods and industry associations and gave them an opportunity to make their views known in writing in accordance with the Rule 6(2);
- vii. The Authority forwarded a copy of the public notice to all the known importers (whose details were made available by petitioner) of Sodium Cyanide in India and advised them to make their views known in writing within forty days from the date of issue of the letter;
- viii. Request was made to the Central Board of Excise and Customs (CBEC) to arrange details of imports of Sodium Cyanide made in India during the past three years, including the period of investigation.
- ix. The Authority provided a copy of the petition to the known exporters and the Embassy of the subject countries in accordance with Rules 6(3) supra. A copy of the petition was also provided to other interested parties, wherever requested;
- x. The Authority sent a questionnaire to elicit relevant information, to the following known exporters, in accordance with the Rule 6(4);

(a) EU

- Degussa Antwerpen N.V., Belgium
- Rhone-Poulenc Fibres- France
- Zeneca Agrochemicals Fernhurst
- Basilur P.A. – Italy
- Enichem S.P.A., Italy
- DSM Business Unit Intermediate- Netherlands
- Energias Industrias Aragonesas, Spain
- Moniplet & Esteban SL, Spain
- Degussa AG – Germany
- BASF-Aktiengesellschaft- Germany
- E.Merck- Germany
- Petro/Chemie B Kraft Stoffe- Germany

(b) USA

- E.I. DuPont de Nemours & Co. Inc., USA
- Degussa Corporation USA
- FMC Corporation Chemical Product, USA
- Sterling Chemical Inc- USA
- C.P. Chemical Inc.- USA

(c) Czech

- Lucebni Zavodyy-Czech Republic

(d) Korea RP

- Tong-Suh Petrochemicals Corp. Ltd- Seoul, Korea
- Taek Wang, Seoul, Korea

xi. The Embassy of the subject countries/territory in New Delhi was informed about the initiation of the investigation in accordance with rule 6(2) with a request to advise the exporters/producers from their country to respond to the questionnaire within the prescribed time. A copy of the letter, petition and questionnaire sent to the exporters was also sent to the Embassies, along with a list of known exporters/producers.

xii. A number of parties requested for extension of time, which was allowed by the Authority by four weeks. The responses received after the extended time have not been considered for determining the preliminary findings.

xiii The following exporters responded:

EU

- * M/s E. Merck
- * M/s Degussa- Huls
- * M/s PCK Raffinerie GmbH

USA

- * M/s Sterling Chemicals
- * M/s C.P. Chemicals inc.

Korea

- * M/s Hanwah Chemicals Corporation

xiv. A questionnaire was sent to the following known importers of Sodium Cyanide calling for necessary information in accordance with rule 6(4);

- M/s Bakul Aromatics Ltd.
- M/s Premier Intermediates (P) Ltd.
- M/s United Phosphorous Ltd.
- M/s Daurla Sugar Works
- M/s Daurala Organics Ltd.
- M/s Cheminor Drugs Ltd.
- M/s Divis Laboratories Ltd.
- M/s Suven Pharmaceuticals
- M/s Sudarshan Drugs & Intermediate Ltd.
- M/s Suvi Chem
- M/s Anis Rasayan P. Ltd.
- M/s Shri Benzophan Inds. Ltd.
- M/s Mitsu Industries Ltd.
- M/s Bharat Rasayan
- M/s Deluxe Metal Processing
- M/s Chemstar Organics Ltd.
- M/s Ankur Agrochem
- M/s Siris Ltd.

xv Response to the questionnaire was filed by the following importers :-

- M/s Bakul Aromatics Ltd.
- M/s Premier Intermediates (P) Ltd.
- M/s Daurala Organics Ltd.
- M/s Cheminor Drugs Ltd.
- M/s Mitsu Industries Ltd.
- Kores India Ltd.

- xvi. Additional information regarding injury was sought from the petitioners, which was also furnished;
- xvii. The Authority conducted on-the-spot investigation at the premises of the petitioner to the extent considered necessary;
- xviii. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file maintained by the Authority and kept open for inspection by the interested parties;
- xix. Cost investigations were also conducted to work out optimum cost of production and cost to make and sell the subject goods in India on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and the information furnished by the petitioner.
- xx. **** in this notification represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules;
- xxi. Investigation was carried out for the period starting from 1st April, 1998 to 31st December, 1998.

B. PETITIONER'S VIEWS

2. The petitioner have raised the following major issues in their petition and their subsequent submissions:-

- (a) The total production of Indian Industry is 5626 M.T. during the period of investigation out of which the share of the petitioner is 78.44%. The petitioner have, therefore, submitted that the application made by them may be treated as made by or on behalf of the domestic industry and they may be treated as the domestic industry under Rule 2(b) .
- (b) The petitioner have claimed Normal Value in the case of the alleged dumping countries, namely USA, Federal Republic of Germany, Czech Republic, Republic of Korea and EU, on the basis of constructed cost of production.
- (c) The petitioner have claimed that European Union could be considered as an exporting territory for determination of Normal Value. They have submitted that Germany is a member of European Union where no Customs Barriers exist among the member countries. There are many other producers

of Sodium Cyanide in the European Union and in view of this, imposition of Anti-Dumping Duty on Germany alone may not be effective in case, duty is not imposed on the entire European Union. Hence, the request by the petitioner to investigate and levy anti-dumping duty on the European Union collectively as a territory and on Federal Republic of Germany individually.

(d) As regards the injury, the following submissions are made by the petitioner :

- (i) that the petitioner constitutes domestic industry within the meaning of Rule 2(b). The injury suffered by them could, therefore, be considered as evidence of material injury suffered by the domestic industry.
- (ii) The petitioner is claiming injury on account of the following :

- increase in imports from the subject countries.
- significant decline in export price from the subject countries.
- increase in market share of the imports/
- significant decline in the selling prices of the petitioner.
- significant decline in profitability.
- significant increase in inventory level.

(e) Further, the petitioner have raised the issue relating to comparison of landed price of imports with the fair selling price on transaction-to-transaction basis. In this regard, they have stated that the export price of Sodium Cyanide from the subject countries declined steeply. The reason for this steep decline is intensified dumping by the exporters from these countries. In view of this, the petitioner have submitted that the comparison of the fair selling price with landed price of imports should be done on transaction to transaction basis. They have submitted that it is necessary as all exports to India might not have caused material injury to the industry. The concern of the industry is only with regard to those exports which have injured the domestic industry. Since the landed value of imports declined significantly, the comparison of the same on weighted average basis would not be appropriate.

(f) Furthermore, the petitioner have requested for recommending anti-dumping duty on variable basis as the weighted average export price during the investigation period may not reflect the extent of injury being suffered by the domestic industry from the dumped imports, especially when there is a steep decline in export price, particularly from Czech Republic and Korea RP.

C. VIEWS OF EXPORTERS, IMPORTERS AND OTHER INTERESTED PARTIES:

3. I. Importers' views:

- (a) The importers of Sodium Cyanide, who use it for manufacturing the drug intermediates for antibiotics, such as Ampicillin, Cephelexin, cephtradin etc., which are exported from India to a great extent, have stated that any increase in import duty on Sodium Cyanide will trigger off cost and price increase of the inter-mediate, which will have a highly adverse effect on the export of Antibiotics. Alternatively, the intermediates manufactured by the domestic industry will be imported thereby damaging the interests of the domestic industry for drug intermediates.
- (b) The petitioner themselves are exporting the subject goods at prices much lower than domestic prices. They wish to take advantage of the fact that there are only two manufacturers of Sodium Cyanide in India and thus, the domestic prices have been artificially maintained at a level much higher than the International prices. Any increase in import duty, coupled with near monopoly situation in India, is bound to result in significant increase in the domestic price of Sodium Cyanide to the great detriment of the drug and drug intermediates industries.
- (c) The cost of production of Sodium Cyanide can't be higher than the prevailing international prices, at which the petitioner themselves are exporting i.e. about Rs. 38,000 to Rs. 40,000 per M.T.
- (d) Further, it is stated that the petitioner have resorted to the use of constructed value to arrive at the Normal Value of the subject goods. The need to use constructed value arises in case of non-market economies. In the present case, no difficulty can be envisaged in obtaining details of Normal value from exporters from the subject countries.
- (e) There are two manufacturers of Sodium Cyanide, the petitioner and M/s Gujarat Alkalies and Chemicals Ltd. The latter have not joined as a co-petitioner presumably because they are more efficient.

- (f) There is a past history of the two domestic manufacturers forming a cartel and indiscriminately increasing the price of Sodium Cyanide as in 1991 when the import of this product was restricted. The 1991 scenario would be repeated if the Anti-Dumping duty is levied on the product.
- (g) It is further stated that the actual production of both the local manufacturers has always been less than the country's requirements in spite of large installed capacity on paper by both the manufacturers. In the past, whenever there was more production, the same was exported at very low prices, presumably subsidised by higher local selling price.
- (h) Some products like Theophylline, Etofylline etc. which use Sodium Cyanide as an input fall under DPCO and the price is fixed by the Government. The DPCO price of these products has been fixed based on the current price of Sodium Cyanide. If the price of this material increases consequent upon the levy of Anti-Dumping duty, the importers have to seek price revision from Government of India which is a very lengthy process and can take upto 2 years.
- (i) If anti-dumping duty is imposed on Sodium Cyanide, the price of Sodium Cyanide will be increased by the two local manufacturers in which case the cost of production of Phenyl Acetic Acid, Potassium Phenyl Acetate, Benzyl Cyanide and Pencillin will go up. Therefore, the domestic industries manufacturing these finished products out of Sodium Cyanide have to suffer by having to close their units on account of non-viability. The request is, therefore, to impose anti-dumping duty on finished items such as Penicillin and their further derivatives in stead of the same on basic input materials such as Sodium Cyanide.

3. II. Exporters' Views :

- (a) The exporters from the Federal Republic of Germany (FRG) have stated that due to the fundamental differences in the market structure and market requirements of the Indian and domestic (EU) market as well as significant differences in quality, the two markets can be treated only as separate. They have denied the allegations of injury as the already higher market share of the Indian producers based on a considerably high import duty base than WTO country average testify their domination of the market.
- (b) The FRG exporters have pointed out that the principal differences between domestic unit selling price and export unit price to India are based on completely different cost structures for both the markets. For Germany, the corporate cost, manufacturing-selling-Administration overhead as well as packing cost are incomparably higher than for India.
- (c) The respondent exporter from Korea have stated that the case of dumping of Sodium Cyanide in India by them is misleading as their cost of production is lower than their domestic selling price and further their export price for Sodium Cyanide are higher than their domestic market prices in Korea.
- (d) The Korean exporter, M/s. Hanwha Chemical Corporation, who have responded to the questionnaire, have submitted that the cost of production of their producing company, namely, M/s Tong Suh Petrochemicals Corporation Ltd. is lower as compared to that of Indian manufacturers for the basic reason that their production facility for Sodium Cyanide is basically a downstream project using the bye products from their Acrylonitrile Plant. The major raw material i.e. HCN Gas used in the production of Sodium Cyanide comes to them as a bye product from the Acrylonitrile production. Further Caustic Soda Lye the prices of which have been falling sharply in the global market, are received by their plant through a pipeline from a plant situated next door. All these factors reduce their cost of production of Sodium Cyanide to a large extent.
- (e) The exporter from FRG have pointed out the differences in the specification and processing for Sodium Cyanide Manufactured by them and the same from the petitioner. Their product is claimed to be manufactured according to the DIN ISO 50971 standard with a content of max. 0.005% insoluble products. The Indian product does not conform to this standard

and has a ten times higher content of insoluble compounds. The Customers of the FR Germany exporter are stated to be specialized in the manufacture of pharmaceutical intermediates and end products, which have to have a high purity and a minimum of impurities of insoluble compounds- during their production. The exporter's product is claimed to fulfil these criteria of purity. In view of this, they do not agree to the petitioner's claim that there are no significant differences in their product and the imported product and that the two are like articles and that the goods are imported due to their availability at dumped prices

- (f) As regards the domestic EU market, it is stated that the marketing efforts differ markedly from those for Indian market. The additional costs involved in the former are on account of cost – intensive charge and discharge of Sodium Cyanide in intermediate bulk containers, a high level of technical advice, Cyanide destruction technology, and compliance with the strict EU environmental regulations. In order to meet the different legal requirements of each member of the EU, they have developed specially designed programs comprising safety instructions for use of Sodium Cyanide, training sessions and surveys of Cyanide ware houses. Their distribution network in the EU is quite extensive and substantial sales force and technical services are necessary to support and supply the highly diversified EU market structure. Therefore, in contrast to the Indian market, the selling costs are significantly higher.
- (f) As to dumping, the FRG exporters have highlighted fundamental differences between their domestic market and the Indian market in terms of infrastructure, supplier- purchaser relationship, the amount of funds spent to conform with the technical and environmental demands of their domestic market. According to them dumping can not be ascertained under Section 9-A(1)(C) on the ground that comparison is not possible between the domestic market cost structure and the same for the Indian market in view of differences in the terms and circumstances of the respective markets.
- (h) In the matter relating to injury the FRG exporter have stated that there is already very high market share of the Indian producers based on a considerably higher import duty base, which indicates the domination of the local producers in Indian market. As regards the price, it is stated that there is a worldwide decline in Sodium Cyanides price as evidenced by the figures from the Chemical Trade Intelligence, India. The Indian Chemical Export Price List shows a FOB prices of US \$

881/MT for the period March-December, 1998. A more detailed export list reveals that the petitioner on the other hand exported at prices ranging from US \$ 835 to US \$ 1000 FOB. This would correspond to US \$ 890-1050 CIF/MT and would be on the lower end of the World market price at that time.

- (i) The FRG exporters have pointed to the drastic decline of the World market prices in the last three years due to stagnant and decreasing demand compared with new production facilities in Asia (about 30000 tonnes/year of additional capacity). As a consequence, none of the producers managed to keep up its price level and had to implement major cost reduction programmes. However, despite this global declining trend, the petitioner not only managed to increase its sales quantity, but also was able to maintain a domestic price which is 35.2% above the World market price of Sodium Cyanide.
- (j) Comparing differences in the specification and processing of Sodium Cyanide from the FRG exporter and the petitioner, the former have pointed to the significant quality and packaging advantages of their product over the petitioner's product.

The costs to support the sophisticated technical and logistical requirement, which are indispensable in order to guarantee a safe handling and supply of Sodium Cyanide in the European market places, includes added values like : Quality and packaging systems; emergency response systems ; Responsive care activities; and Patented technologies such as control systems, detoxification systems to optimise the usage of Cyanide, as an integral part of the domestic selling price of the exporters. Thus, the exporter's argument is that their domestic market (EU) and the Indian market are characterised by such fundamental differences that Normal Value can not be ascertained on the basis of domestic sales price. Therefore, their contention is that there is no dumping from them.

- (k) The petitioner have not suffered injury as :
- The Indian producers already have a very high market share of well above 80% and domination in the market based on a considerably higher import duty base.
 - On price front, there is a decline of World market price which has also an impact in the Indian market.
 - Contrary to the petitioner's claim, the petitioner's sales volume in the domestic industry has shown an increase of 587 tonnes

or 14% in the last three years as per the evidence provided by themselves.

- (I) On the question of Causal link, it is stated that contrary to the petitioner's claim, the demand in Indian market has increased by 833 Tonnes or 11.94% between 1995-96 and 1998-99 which is a considerable increase compared to World market decline of roughly 5%. Whereas the percentage figures of market share of the domestic producers declined marginally from 86.09% to 81.87%, the actual quantity sold increased by 15.7 tonnes.

Further, it is stated that there are evidences that Indian producers have quoted their exports at prices far below the prices generated by them, i.e. the FRG exporter, in Indian market and at the low end of the World market price. This evidence disputes the fact that the material is dumped in India and that the petitioner suffered injury from imported material.

(D) Examination of the issues raised

4. The foregoing submissions made by the exporters, the importers, the petitioner and other interested parties, to the extent these are relevant as per Rules and to extent these have a bearing upon the case, have been examined and considered and have been dealt with at appropriate places in these findings.

(E) Product under consideration

5. The product involved in the present investigation is Sodium Cyanide originating in or exported from the subject countries classified under Customs Sub heading 2837.11 of Customs Tariff Act. The classification is only indicative and in no way binding on the scope of present investigation. Sodium Cyanide is a pure, basic inorganic chemical. It is manufactured by reacting Hydrocyanic Acid (HCN) with Caustic Soda. It is mainly used in extraction of gold from gold ores. Pharmaceuticals and pesticides industries also use it as intermediates. It is also used by industries such as dye intermediates, electroplating chemicals and for manufacture of Heat treatment salts.

(F) Like articles :

6. The petitioner have claimed that there are no significant differences in their product and the same imported from the said countries, which can have impact on price and quality. The two are comparable in terms of physical and chemical

characteristics (size, chemical composition), manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, distribution and marketing and tariff classification of goods.

The two are technically and commercially substitutable. Importers are interchangeably consuming imported and domestic Sodium Cyanide. The two are, therefore, Like Articles within the meaning of the Anti-Dumping Rules. In this regard, it is observed by the Authority, that though some exporters have claimed differences of their product in processing, quality and packaging over the petitioner's product, these differences do not have any impact on the likeness of two products as both are used by the importers and consumers interchangeably. The Authority finds that both have the same end-uses and both have the similar fundamental technical characteristics. The quality superiority of the imported product in terms of lower heavy metal concentrations and water content as well as lower content of insoluble compounds vis-à-vis the Indian product does not make any difference in the basic technical characteristics of both. The differences are only in degree and not in kind. Thus, the Authority observes that the Sodium Cyanide produced by the domestic industry in India has characteristics closely resembling the same of the Sodium Cyanide imported from the subject countries. Both are technically and commercially substitutable and, therefore, are treated as Like Articles under the meaning of the Anti-Dumping Rules.

(G) Domestic Industry

7. The petition has been filed by M/s Cyanides and Chemicals Company., 65, Free Press House, Nariman Point, Mumbai. There is only one more producer of Sodium Cyanide in India, namely, M/s Gujrat Alkalies and Chemicals Ltd.. The total production of Sodium Cyanide in India during the POI was 5628 M.T. out of which the petitioner produced 4413 M.T. of Sodium Cyanide. Thus, the petitioner accounts for more than 25% of domestic production of Sodium Cyanide and, therefore, the Authority notes that they (the petitioner) have the requisite standing to file the petition on behalf of the domestic industry under the Rules.

H. Dumping

8. Under Section 9A(1)(c), normal value in relation to an article means:

- (i) The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting

country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section(6) ; or

- (ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either.
 - (a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or
 - (b) the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6);

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transhipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

9. The Authority sent questionnaires to the exporters from the subject countries in terms of the section cited above. The claim made by the exporters with regard to normal value and export price are as under:

I. Claims of the exporters on Normal Value and Export price

10. (a) EU

Exporter : PCK Raffinerie GmbH

The exporter have claimed that they have not exported any Sodium Cyanide to India during the specified period i.e. 1st April, 1998 to 31st December, 1998 and that their production of Sodium Cyanide has ceased on 30th June, 1998. They do not consider it necessary to fill in the questionnaire.

Exporter : E. Merck

The exporter have stated that they have not invoiced or sold Sodium Cyanide to any party in India. Thus they will not fill in the questionnaire.

Exporter - M/s Degussa Huls

The exporter have furnished information in respect of Sodium Cyanide in relation to the domestic price and export price to India.

Normal Value:

The exporter have claimed normal value on the basis of weighted average selling price in respect of domestic sales in the entire E.U. (E.U. is considered as the domestic market) and the adjustments thereon. The adjustments are claimed on account of commission, insurance, interest and freight. Thus the normal value, i.e. the domestic selling price at ex-factory level is claimed as US\$ xxxx/M.T.

Export Price:

The export price to India is claimed on the basis of weighted average cif value of exports to India during the period of investigation. Adjustments are claimed on account of commission, FOB cost, interest, ocean freight and insurance. Accordingly export price at ex-factory level is claimed as US\$ xxxx/M.T.

The delegation of European Commission and other exporters from the EU (other than M/s Degussa Huls) have not furnished any information on Normal Value and Export price for the subject goods exported by the exporters of their member countries, which are essential for determination of dumping and dumping margin. Therefore, the Authority considers the informations provided by the petitioner in this regard.

(b) Korea RP

Producer : Tong Suh Petrochemicals Corporation Ltd.

and

Exporter : Hanwha Chemical Corporation Ltd.;

The exporter have submitted information regarding the domestic as well as export price.

Normal value:

The exporter have claimed normal value on the basis of average selling price in respect of domestic sales during the period of

investigation and adjustments thereon. Adjustments are claimed on account of local transportation, insurance, value added tax and agency commission. In evidence of domestic selling price, the exporter have furnished copies of two domestic invoices. The average domestic selling price is claimed as US\$ xxxx/M.T. during the relevant period. Taking this into account and the adjustments claimed thereon, the normal value is claimed as US\$ xxxxx/M.T.

Export price:

Here the average export price (cif) to India is claimed as US\$ xxx/M.T. and adjustments are claimed on account of local transportation cost in Korea (factory to port), Ocean freight to India, insurance, container tax, handling charges and margins for agents. Thus the export price at ex-factory level is claimed as US\$ xxxxxx/M.T.

(c) USA

Exporter : Sterling Chemicals

The producer/exporter have stated that they are not a proper party in the present investigation. They claim to be owned by E.I. Dupont and they only produce the subject goods. They do not sell, export or any way market the Sodium Cyanide produced by them. Thus, they claim that they are not a proper party in the investigation.

Exporter/Manufacturer : C.P.Chemicals.

It is stated that C.P. Chemicals has at no time before, during or after the relevant period 1st April, 1998 to 31st December, 1998, either manufactured or exported Sodium Cyanide.

Thus the Authority finds that no exporter/producer from USA have responded to the questionnaire nor have furnished the requisite information on Normal value and export price. Therefore, the Authority considers the information provided by the petitioner and the export price from DGCIS source as the best available information.

(d) Czech Republic:

No exporter/producer from Czech Republic have furnished the requisite information on Normal Value and export price. Therefore, the petitioner's informations on these and export price from DGCIS source are considered by the Authority and, accordingly the Authority determines the Normal value and Export price.

J. Examination of the claims of the Exporters by the Authority:

11. The claims of various exporters in respect of Normal value and export price are examined as under :

(a) USA:

Though two producers/exporters from USA have responded, the Authority notes that no exporter/producer have submitted information on normal value and export price in respect of the product under consideration. Therefore, the Authority considers the information provided by the petitioner and the export price from DGCIS source as best available information and determines Normal value and export price at US\$ 1450/M.T. and at US\$ 760/M.T. respectively. Thus, the dumping margin is calculated as US\$ 690/M.T. which is 90.78% of export price.

(b) EU

Exporter : M/s Degussa Huls

Here, the Authority notes that the exporter have claimed Normal value on the basis of weighted average domestic price of their sales in the various member countries of the European Union, which as a whole is claimed as the domestic market by the exporter. The Authority also admits the amounts towards adjustments on account of commission, Insurance, interest and freight claimed by the exporter. Thus the Authority determines the Normal Value at US\$ *** /M.T. for the purpose of Preliminary determination subject to verification.

In respect of the export price, the Authority notes that the same is claimed by the exporter on the basis of weighted average cif value of exports to India. The Authority allows the adjustments claimed on account of commission, FOB costs, interest, Ocean freight and insurance. The Authority, thus, determines the export price at US\$/M.T. as claimed by the exporter subject to verification. The dumping margin is calculated as US\$ xxxx/M.T. which is 37% of the export price.

The Authority notes that neither the exporters/producers of EU member states (except those mentioned in para A.1.xiii) nor the EC delegation have responded to the questionnaire nor have they furnished informations in relation to Normal Value and export price of Sodium Cyanide. The Normal value and export price in respect of all non cooperative exporters of the European Union and the dumping

margin is, therefore, based on the information provided by the petitioner.

The Authority states that while the case was initiated on the request of the petitioner against the FRG and the European Union, considering that FRG is a part of the European Union and the latter is a territory with no trade and tariff barriers, the case has been examined with respect to all the exporters of EU as a territory.

(c) Czech Republic :

The Authority notes that no producer/exporter have submitted requisite information on normal value and export price in respect of the product under consideration. Therefore, the Authority considers the information provided by the petitioner and the export price (cif) from the DGCIS source as best available information and determines normal value and export price at US\$ 1581/M.T. and at US\$ 912/M.T. respectively.

Thus, the dumping margin is determined as US\$ 669/M.T. which is 73.35% of export price.

(d) Korea RP

Exporter : M/s Hanwha Chemical Corporation.

Producer : M/s Tong Suh Petrochemical Corporation Ltd.

The Authority notes that the exporter have claimed Normal value on the basis of average domestic selling price and adjustments on account of local transportation, insurance, value added tax and agency commission. These adjustments are allowed by the Authority. The Authority also notes that in evidence of domestic selling price, the exporter have furnished copies of two invoices pertaining to the POI. The Authority further notes that production of Sodium Cyanide in this case is a down-stream process using some bye products of another plant of the producer as raw-materials for Sodium Cyanide, thereby reducing the cost of production. The Authority, therefore, determines the Normal value at US\$*****/M.T. for the purpose of preliminary determination which is subject to verification.

The export price is claimed on the basis of weighted average export price to India which, the Authority finds, matches with DGCIS data. Adjustments are claimed on account of local freight in Korea, Ocean freight, insurance, container tax and handling charges and commission for India. These expenses as claimed are allowed by the Authority for preliminary determination subject to verification.

The export price is, thus, determined at US\$*****/M.T. subject to verification. The Authority finds that the comparison of Normal value and export price so determined shows nil dumping margin.

Non-Cooperative Exporters

In respect of non-cooperative exporters from subject countries/territory who have not responded to the questionnaire, the Authority determines the dumping margin at the same claimed by the petitioner for the respective country/territory as a whole on the basis of their (petitioner's) information on Normal value and export price.

Thus the dumping margin as % of ex-factory export price in respect of subject countries/territory and the exporters are determined as follows :

Country	Exporter	Dumping Margin
1. USA	All Exporters	90.78%
2. E.U.	M/s Degussa Huls All other Exporters	37% 54%
3. Czech Republic	All Exporters	73.35%
4. Korea RP	M/s. Hanwha Chemical Corpn. and M/s. Tong Suh Petrochemicals Corporation Ltd. All other Exporters	NIL 89.20%

K. INJURY

12. Under Rule 11 supra, Annexure-II, when a finding of injury is arrived at, such finding shall involve determination of the injury to the domestic industry, "taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such article..." In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increase, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

Annexure II(iii) under rule 11 supra further provides that in case where imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to Anti dumping investigation, the Designated Authority will cumulatively assess the effect of such imports, only when it determines that the margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than two percent expressed as percentage of export price and the volume of the imports from each country is three percent of the imports of the like article or where the export of the individual countries less than three percent, the imports cumulatively accounts for more than seven percent of the imports of like article, and cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic articles.

The Authority notes that the margin of dumping and quantum of imports from subject country are more than the limits prescribed above. Cumulative assessment of the effects of imports is appropriate since the export prices from the subject countries were directly competing with the prices offered by the domestic industry in the Indian market.

For the examination of the impact of imports on the domestic industry in India, the Authority has considered such further indices having a bearing on the state of the industry as production, capacity utilization, sales quantum, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping etc. in accordance with Annexure II(iv) of the rules supra.

(a) Quantum of imports:

The Authority has considered the statistics of the petitioner and the same published by DGCIS, Calcutta in this regard and finds that there is a marginal variation between the both. However, the Authority has relied upon the data relating to import volume, as published by DGCIS, Calcutta, which is a Governmental body, to analyse the import trend from the subject countries and the injury caused to the domestic industry on this count.

As per the statistics published by DGCI and S, the quantum of imports during the last three years and during the POI is as under :

	<u>1995-96</u>	<u>1996-97</u>	<u>1997-98</u>	(In M.Ts) <u>POI</u> (annualised)
From subject Countries:	890	1210	1393	1245 (1660)
From others :	148	304	371	100 (133)
Total :	1038	1514	1764	1345 (1793)

From the above figures, it is observed that (a) the Volume of total imports from the subject countries has registered an increase of 86.5% during the POI (on annualised basis) in absolute terms over 1995-96 (b) the volume of imports from the subject countries constituted 85%, 80%, 79% and 93% of total imports during 1995-96, 96-97, 97-98 and the POI respectively.

(b) Production capacity and capacity utilisation:

The petitioner have stated that they are having an installed capacity of 6372 M.T. which has not changed during the last three years. There is no significant change in production over the years. The capacity utilisation has been 89.78% during 1995-96, 87.29% during 1996-97, 86.94% during 1997-98 and 92.34% during the POI.

(c) Volume of sales and market share:

The volume of sales of the domestic industry which was 4201 M.T. during 1995-96 has increased to 4761 M.T. during the POI (annualised). The market share of the domestic industry, which was 74.3% during 1996-97, increased to 79.5% during 1997-98 and declined to 72.35% during the POI.

(d) Employment :

It is observed that there is a decline in manpower employed with the petitioner from 334 employees during 1996-97 to 317 during 1998-99.

(e) Average sales realisation and profitability:

The average sales realisation was Rs...../M.T. during 1995-96, Rs...../M.T. during 1996-97, Rs...../M.T. during 1997-98. It declined in the year 1997-98 to Rs...../M.T. from Rs...../M.T. during 1996-97. During the POI, it is observed that the average sales realisation declined further to Rs...../M.T. It is observed that the petitioner has incurred loss during both 1997-98 and the POI and the loss per M.T. has increased from Rs...../M.T. during 1997-98 to Rs...../M.T. during the POI, i.e. April-December, 1998.

L. Conclusion on Injury:

13. In the light of the above observations on injury parameters, the following conclusions are arrived at :

- (a) Quantum of imports from the subject countries and total imports have increased during the POI as compared to the period 1995-96.
The market share of imports from the subject countries increased from 21.54% during 1996-97 to 25.32% during the POI.
- (b) The production and capacity utilisation have been stable over the years.
- (c) There has been a marginal reduction in the number of employees with the petitioner.
- (d) The petitioner's volume of sales in absolute terms was higher during the POI as compared to the period 1995-96. However, the market share of the petitioner has declined during the POI compared to the previous years due to increase in imports from the subject countries.
- (e) There has been a decline in average selling price of the subject goods during the POI as compared to the previous year of 1997-98. This has resulted in the increase of losses suffered by the petitioner during the POI.

All the above factors, namely, increase in quantum of imports from subject countries, decline in market share, decline in employment, decline in average sales realisation and increase in the

losses incurred, suggest that the domestic industry has suffered material injury.

M. Causal link

14. In establishing that the material injury to the domestic industry has been caused by the imports from subject countries, the Authority holds that increase in quantum of imports from subject countries resulted in decline in the market share of petitioner. This had the effect of under cutting the prices of domestic product forcing the domestic industry to sell below its fair selling price. Resultantly, the domestic industry was not in a position to realise its fair selling price and, therefore, incurred losses. The material injury to the domestic industry was, therefore, caused by the dumped imports from the subject countries.

N. Indian Industry's interest and other issues

15. The purpose of anti dumping duties, in general, is to eliminate dumping which is causing injury to the domestic industry and to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country.
16. It is recognised that the imposition of anti dumping duties might affect the price levels of the products manufactured using the subject goods and consequently might have some influence on relative competitiveness of these products. However, fair competition on the Indian market will not be reduced by the anti dumping measures, particularly if the levy of the anti dumping duty is restricted to an amount necessary to redress the injury to the domestic industry. On the contrary, imposition of anti dumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practices, would prevent the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of Sodium Cyanide. Imposition of anti dumping measures would not restrict imports from the subject countries in any way, and, therefore, would not affect the availability of the product to the consumers.
17. To ascertain the extent of anti-dumping duty necessary to remove the injury to the domestic industry, the Authority may rely upon reasonable selling price of Sodium Cyanide in India for the domestic industry, by considering the optimum cost of production at optimum level of capacity utilisation for the domestic industry.

O. Conclusions

- 18.** After considering the foregoing, it is seen that :
- (a) Sodium Cyanide described under para 5 and originating in or exported from Czech Republic, USA, Korea RP and EU except that originating in or exported by M/s Hanwah Chemicals Corporation and M/s Tong Suh Petrochemicals Ltd. of Korea RP has been exported below normal value, resulting in dumping.
- (b) The Indian Industry has suffered material injury.
- (c) The injury has been caused cumulatively by the dumped imports from the subject countries.
- 19.** It is considered necessary to impose anti-dumping duty provisionally, pending final determination, on all imports of Sodium Cyanide originating in or exported from the subject countries.
- 20.** The Authority considered to recommend the amount of Anti-Dumping Duty equal to the margin of dumping or less, which if levied, would remove the injury to domestic industry. The average landed price of the imports, for the purpose, was compared with the Non-injurious selling price of the petitioner determined for the period of investigation. Wherever the difference was less than the dumping margin, a duty lower than the dumping margin is recommended. Accordingly, it is proposed that provisional anti dumping duties be imposed, from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government, on all Sodium Cyanide originating in or exported from USA, Czech Republic, Korea RP and EU falling under Customs sub-heading No. 2837.11 of the Customs Tariff Act, pending final determination.
- 21.** The Anti-Dumping duty in respect of subject countries/territory and the exporters shall be the amounts mentioned in column 4 of the following table :

Sl.No.	Country	Exporter	Amount (Rupees per MT)
1.	USA	All exporters	401
2.	E.U.	1. M/s. Degussa Huls 2. All other exporters	No duty 3339
3.	Czech Republic	All exporters	2470
4.	Korea RP	1. M/s. Hanwah Chemicals Corpn. 2. M/s. Tong Suh Petrochemicals Corp. Ltd. 3. All other Exporters	No duty No duty 11460

22. Landed value of imports for the purpose shall be the assessable value as determined by the Customs under the Customs Act, 1962 and all duties of customs except duties levied under Section 3, 3A, 8B, 9 and 9 A of the Customs Tariff Act, 1975.

P. FURTHER PROCEDURE:

23. The following procedure would be followed subsequent to notifying the preliminary findings:

- (a) The Authority invites comments on these findings from all interested parties and the same would be considered in the final findings;
- (b) Exporters, importers, petitioners and other interested parties known to be concerned are being addressed separately by the Authority, who may make known their views, within forty days of the despatch of this notification. Any other interested party may also make known its views within forty days from the date of publication of these findings.
- (c) The Authority would disclose essential facts before announcing the final findings.

RATHI VINAY JHA, Designated Authority